सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" जिसके मन में विश्वास और दिल में सच्चाई होती है
उसकी राह में आने वाली मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है... !!
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–300 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 21 नवंबर 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

कुंडा में राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन, फिर भी क्यों नहीं गए सीएम योगी? गोंडा की कथा और अखिलेश पर निशाने की पूरी इनसाइड स्टोरी

आलोक तिवारी / लखनऊ-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों धार्मिक आयोजनों और रामकथाओं के इर्द-गिर्द घूम रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा का आयोजन कराया। इस मंच पर देश भर के दिग्गज ठाकुर नेताओं और सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों का जमावड़ा लगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन से दूर रहे।

गोंडा की कथा, बाबा रामदेव और बृजभूषण का समीकरण : 17 नवंबर से एक तरफ कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुरू हुई, तो दूसरी तरफ गोंडा में आलोक दास महाराज के संयोजन में राजन जी महाराज की रामकथा का आगाज हुआ। इस कथा की शुरुआत में खुद धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए थे। योग गुरु बाबा रामदेव के न्योते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति भी दे दी थी। गोरखपुर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम के बाद उन्हें गोंडा जाना था, लेकिन मंच से भाषण खत्म होते ही माता जी के निधन की दुखद सूचना मिलने के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द कर पैतृक गांव जाना पड़ा।



इस गोंडा वाली कथा के पीछे गहरा चुनावी गणित छिपा है। आयोजक आलोक दास (जिनका चित्रकूट से हरिद्वार तक ट्रस्ट का विस्तार है) बाबा रामदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी नजर गोंडा की तरबगंज व मेहनौन विधानसभा सीटों पर है। सियासी गलियारों में माना जाता है कि गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है। यही वजह है कि कभी पतंजलि और अन्य मुद्दों पर बृजभूषण शरण सिंह व बाबा रामदेव के बीच रही तल्खी अब दोस्ती में बदलती दिखी और कुंडा के मंच पर दोनों के गले मिलने की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं।

अखिलेश के विरोध के बीच राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन : यूपी की राजनीति में अब धार्मिक कथाएं चुनावी माहौल और हिंदुत्व की पिच तैयार करने का बड़ा जरिया बन गई हैं। हाल ही में भगवान राम और श्रीकृष्ण को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसे कार्यक्रमों के बहिष्कार की अपील की थी। इसी विवाद के बीच राजा भैया ने कुंडा में इस भव्य आयोजन के जरिए सीधा सियासी संदेश दिया।



मंच से राजा भैया ने खुद बताया कि प्रयागराज से हेलीकॉप्टर सीधे कुंडा उतर सकता था, लेकिन सपा के संभावित विरोध की वजहों के बीच वे धीरेंद्र शास्त्री को खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर कुंडा लाए, ताकि यह देखा जा सके कि विरोध कौन करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के गुलशन यादव के खिलाफ राजा भैया की जीत का अंतर करीब एक लाख से घटकर लगभग 30 हजार के आसपास सिमट गया था। ऐसे में इस कथा को प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज बेल्ट में हिंदुत्व की पिच मजबूत करने और अखिलेश यादव के PDA समीकरण की काट तैयार करने की कोशिश माना जा रहा है।



दिग्गजों का जमावड़ा और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश : कुंडा के मंच पर बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, अभिजीत सांगा, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, राजस्थान के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह जैसे चेहरे पहुंचे। इसे 'ठाकुर शक्ति प्रदर्शन' के तौर पर देखा गया, हालांकि सामाजिक संतुलन दिखाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री मनोज पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद निशिकांत दुबे और विधायक दीपक पटेल जैसे नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा, वर्षों बाद राजा भैया और धनंजय सिंह का एक ही मंच पर साथ दिखना भी चर्चा का विषय रहा, जिनके बीच मुलायम सरकार के गठन के दौर में हुए सियासी विलय को लेकर पुरानी दरार थी।

बीजेपी से गठबंधन की चाहत और काउंटर पोलराइजेशन का खतरा : कल्याण सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकारों में मंत्री रहे राजा भैया पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। वे अपनी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते हैं - 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इसे लेकर कोशिशें हुई थीं, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब एक बार फिर इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए वे बीजेपी नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराते दिख रहे हैं। हालांकि, सियासी जानकारों का मानना है कि यदि इस आयोजन की छवि केवल एक जाति विशेष के शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रही, तो इससे यूपी की राजनीति में काउंटर पोलराइजेशन (विपरीत ध्रुवीकरण) का खतरा भी पैदा हो सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक



नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि माँ का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। एक पुत्र के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ का निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा केदारनाथ से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

रायपुर रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर रहने वाली 2 वर्षीय बालिका की मौत, परिजनों की मांग पर होगा पोस्टमार्टम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर रहने वाली 25 वर्षीय महिला की लगभग 2 वर्षीय पुत्री की उपचार के दौरान मेकाहारा अस्पताल में मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा मृत्यु को संदेहास्पद बताने पर अब पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

क्या हुआ था? : 19 नवंबर 2026 को प्रातः लगभग 8–9 बजे रेलवे स्टेशन रायपुर के फुटपाथ पर (जीआरपी क्षेत्राधिकार) निवासरत महिला की 2 वर्षीय पुत्री की तबीयत खराब होने पर उसे उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान दोपहर लगभग 2 बजे बालिका की मृत्यु हो गई।

पहले सामान्य बीमारी से मौत मानी गई : प्रारंभिक तौर पर मृत्यु सामान्य बीमारी के कारण होना प्रतीत होने तथा उस समय परिजनों द्वारा किसी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं किए जाने से मेकाहारा अस्पताल की चिकित्सकीय टीम ने परिजनों को मृत्यु की सूचना देकर नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए डिस्चार्ज किया था।

अब परिजनों ने की पोस्टमार्टम की मांग : बाद में बालिका की माता एवं परिजनों ने मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में परिजनों से पृथक आवेदन प्राप्त कर बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की प्रक्रिया की जा रही है। वर्तमान में चिकित्सकीय टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही मृत्यु के वास्तविक कारण एवं अन्य किसी संदेहास्पद परिस्थिति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अकवान की बेमौसम बारिश से छत्तीसगढ़ प्रदेश हुआ बेहाल : पारा 9 डिग्री तक लुढ़का

खेतों में डूबी धान की फसल, किसानों पर पड़ी दोहरी मार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर



बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। पहले अर्नव और अब अकवान – दो तूफानों की दोहरी मार से किसान सबसे ज्यादा बेहाल हैं। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार रात तक जारी रहा। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और बारिश हुई, जिससे दिन का तापमान सामान्य से 5 से 9 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया। बेमौसम बारिश और जलभराव से धान की कटाई व मिसाई प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा खतरा उन किसानों की फसल पर है, जिन्होंने धान काटकर खेत में छोड़ दिया है। खड़ी फसल भी बारिश और तेज हवा से प्रभावित हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है और इसके स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। रविवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कोरबा के लिए दो दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

कहां कितनी बारिश, कितना गिरा पारा

बारिश के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 30 मिमी वर्षा नया बागद्वार में दर्ज की गई। रायगढ़ में 24 घंटे में 26 मिमी, बसना, हुरा, बागबाहरा और मालखरौदा में 20 मिमी तथा कोरबा में औसतन 10 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सरायपाली, पिथौरा, शिवरीनारायण, कोमाखान, चंद्रपुर, बम्हनीडीह, महासमुंद, नवागढ़, गरियाबंद, गोबरा नवापारा, भैंठिया, राजिम, हसौद और पलारी में 10 मिमी तक बारिश दर्ज की गई।

अधिकांश प्रमुख केंद्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। माना एयरपोर्ट में 20.9 डिग्री (सामान्य से 9.3 डिग्री कम), रायपुर में 21 डिग्री (सामान्य से 9 डिग्री कम), बिलासपुर में 21.6 डिग्री (सामान्य से 8.4 डिग्री कम), दुर्ग में 23 डिग्री (सामान्य से 6.9 डिग्री कम), पेंड्रारोड में 20.6 डिग्री (सामान्य से 6.5 डिग्री कम) और जगदलपुर में 23.7 डिग्री (सामान्य से 5.5 डिग्री कम) दर्ज हुआ। वहीं कोरबा में अधिकतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 23 डिग्री रहा, जबकि अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सामान्य के बराबर रहा।

तेंदूकोना में खेत बने तालाब

शुक्रवार को दैनिक भास्कर की टीम ने रायपुर से लगे अभनपुर और महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र के तेंदुकोना में पहुंचकर खेतों की स्थिति देखी। महासमुंद जिले के बागबाहरा इलाके में पिछले 24 घंटे में 20 मिमी से अधिक बारिश हुई है। इसका असर सीधे तौर पर खेतों में नजर आ रहा है।

तेंदूकोना के किसान संजय ने 15 एकड़ में धान की फसल लगाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। खेतों में इतना पानी भर गया है कि धान की कटाई फिलहाल संभव नहीं है। इसी तरह कमलीदादर के किसान मनीराम साहू ने बताया कि खेतों में अत्यधिक पानी भर चुका है। सुबह से खेतों से पानी निकालने का काम जारी है। कटी हुई फसल खेतों में ही थी, जो खराब होने की स्थिति में है। बढ़ईपाली के किसान नंदू साहू का कहना था कि खेत में कटी हुई फसल पूरी तरह डूब गई थी।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक नजर में : 18 नवंबर की स्थिति के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,44,405 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।

बारिश के चलते बीज की क्वालिटी होगी खराब: कृषि-मौसम वैज्ञानिक

कृषि-मौसम वैज्ञानिक जीके दास के अनुसार, मौसम की मार सबसे ज्यादा उन किसानों पर पड़ेगी, जिन्होंने फसल काटकर खेतों में छोड़ दिया था। यही नहीं जो धान कटने को है, उसमें भी मौसम का असर होगा। तेज हवा चलने से धान गिरेंगे। बारिश के चलते बीज की क्वालिटी भी खराब होगी। धान में ज्यादा नमी के चलते चावल की क्वालिटी खराब होगी। वहीं मिलिंग में चावल टूटने की समस्या ज्यादा आएगी। धान के अलावा बारिश का असर दलहन-तिलहन की फसलों में भी देखने को मिलेगा। मौसम साफ होते ही सब्जी-भाजी में कीट प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में किसान बारिश के तत्काल बाद उपचार शुरू करें।

कर्ज लेकर की खेती, अब फसल अंकुरित होने का डर

1.60 एकड़ रकबे में धान की फसल लगाई थी, जो अब पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति में है। पहले आए अर्नव तूफान के कारण फसल पानी में डूब गई थी। अब पूरी फसल कट चुकी है, जिसमें से आधी को ही सहेजा जा सका है, जबकि आधी फसल खेत में ही कटी पड़ी है। खेती में अब तक करीब 25 से 30 हजार खर्च हो चुके हैं।

चैनू राम धृतलहरे, भोघले

16 एकड़ की फसल पर संकट, 2 लाख की लागत फंसी

16 एकड़ में धान की खेती की है, जिसके लिए बैंक से 70 से 75 हजार का कर्ज लिया है। अब तक करीब 2 लाख खर्च हो चुके हैं। वर्तमान में 3 एकड़ की कटी हुई फसल खेत में पड़ी है, जबकि 13 एकड़ की फसल अभी भी खेत में खड़ी है। जो फसल कट चुकी है, उसके भीगने से अंकुरित होकर खराब होने का डर है।

कवल सिंह सेन, मगरलोड पठार

पड़ोसन ने दिया चोरी को अंजाम, ब्याज में पैसा कमाने के लिए तोड़ा पेटी का ताला



नई दृष्टिबिंदु / पाटन-दुर्ग

थाना पाटन क्षेत्र के दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में घर से सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पड़ोस में रहने वाली महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी के जेवरात, नगदी एवं वाहन सहित लगभग 10 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की गई है।

क्या था मामला? : 17 नवंबर 2026 को प्रार्थिया कल्याणी देवांगन, उम्र 46 वर्ष, निवासी मकान नंबर 82, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, बिजली ऑफिस के पीछे, पाटन ने थाना पाटन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके घर के कमरे में रखी पुरानी पेटी का ताला एवं कुंदा टूटा हुआ था। पेटी में रखे उनके, उनकी बहन एवं माता के पुराने इस्तेमाली सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम गायब थी। रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 379/2026, धारा 305(क), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

ऐसे हुआ खुलासा : विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थिया एवं परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। प्राप्त जानकारी एवं संदेह के आधार पर प्रार्थिया के घर नियमित रूप से आने-जाने वाली पड़ोसी ज्योतिका सिंह से पूछताछ की गई। पूछताछ में ज्योतिका सिंह ने अपने परिचित लव कुमार साहू के कहने पर ब्याज में पैसा कमाने के उद्देश्य से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम चोरी करना बताया।

आरोपिया ने चोरी किए गए कुछ जेवरात ज्वेलर्स दुकान में बेचकर नगदी प्राप्त करना तथा प्राप्त रकम एवं जेवरात अपने पति मयूर उर्फ आकाश सिंह अवधिया एवं परिचित लव कुमार साहू को देना बताया। पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम, मोबाइल फोन एवं दोपहिया वाहन बरामद किए।

ACCU एवं थाना पाटन की संयुक्त टीम ने तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरी की घटना का खुलासा किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी में ज्योतिका सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम गोडपेण्डी, थाना उतई, जिला दुर्ग, वर्तमान पता दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, बिजली ऑफिस के पीछे, पाटन, मयूर उर्फ आकाश सिंह अवधिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गोडपेण्डी, थाना उतई, जिला दुर्ग, वर्तमान पता दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, बिजली ऑफिस के पीछे, पाटन और लव कुमार साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 03, दाउबाड़ा, नंदिनी, अहिवारा, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग।

क्या-क्या बरामद हुआ?

ज्योतिका सिंह से - एक्टिवा वाहन CG-07-DG-0724 (60,000 रु.), वनप्लस मोबाइल (25,000 रु.), सोने के झुमके, ईयरिंग, गेहू दाना, गोला दाना, टॉप्स, नगदी 13,000 रु. सहित कुल 2,95,600 रु. की संपत्ति।

मयूर उर्फ आकाश सिंह से - मोटरसाइकिल (65,000 रु.), रेडमी मोबाइल, चांदी की चेन, नगदी 6,000 रु. सहित कुल 89,500 रु. की संपत्ति।

लव कुमार साहू से - सोने के टॉप्स, वनप्लस मोबाइल, चांदी का ब्रेसलेट, लॉकेट, नगदी 7,000 रु. सहित कुल 67,260 रु. की संपत्ति।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि घरों में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं कीमती सामान सुरक्षित स्थान पर रखें। घर में आने-जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सतर्कता बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा चोरी की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को दें।

आईजी बस्तर ने किया बीजापुर का दो दिवसीय वार्षिक निरीक्षण, पुलिस दरबार में सुनीं जवानों की समस्याएं

नई दृष्टिबिंदु / बीजापुर





पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा ने 19 व 20 नवंबर को जिला बीजापुर का दो दिवसीय वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विभिन्न शाखाओं, पुलिस परेड, वाहन शाखा एवं डॉग स्क्वाड का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस दरबार लेकर जवानों की समस्याएं सुनीं।

एसपी कार्यालय का निरीक्षण

निरीक्षण के प्रथम दिवस पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बीजापुर का निरीक्षण किया और जिले के राजपत्रित अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में स्वीकृत एवं उपलब्ध बल तथा रिक्त पदों की स्थिति, पंजीबद्ध अपराधों और लंबित अपराधों की प्रगति, तथा लंबित मर्ग प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीसीटीएनएस डैशबोर्ड, समय पर डाटा एंट्री, साइबर अपराधों से जुड़े पोर्टल CEIR (गुम/चोरी मोबाइल की ट्रैकिंग) एवं टफ्ट पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। आम नागरिकों से जुड़े इन ऑनलाइन पोर्टलों पर प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस महानिरीक्षक ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर अभिलेखों के संधारण एवं कार्यप्रणाली की जानकारी ली। माओवाद के खात्मे के बाद क्षेत्र में डिमाइनिंग और माओवादियों द्वारा छिपाए गए डम्प की रिकव्हरी पर भी विशेष चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीणों एवं सुरक्षा बलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाने हेतु डिमाइनिंग अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाए।

पुनर्वासित माओवादियों से की मुलाकात

पुनर्वास केन्द्र में पुनर्वासित माओवादियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की गई तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जुड़कर शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने और बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान शासन की पुनर्वास नीति एवं कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

परेड निरीक्षण एवं पुलिस दरबार

निरीक्षण के द्वितीय दिवस पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने जवानों की वेशभूषा, परेड, वाहन शाखा के वाहनों और डॉग स्क्वाड का निरीक्षण किया। इसके पश्चात आयोजित पुलिस दरबार में पुलिस महानिरीक्षक जवानों से सीधे रूबरू हुए। उन्होंने जवानों से चर्चा कर उनकी व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याएं सुनीं, और प्राप्त प्रतिवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक ने जिला पुलिस बीजापुर के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को जनता से बेहतर समन्वय रखते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास के लिए निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए।



48वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का दूसरा दिन : भारतीय भाषाओं में विज्ञान शिक्षा पर हुआ मंथन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आयोजित 48वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस के दूसरे दिन विभिन्न अकादमिक गतिविधियों, प्लेनरी व्याख्यानों एवं शोध पत्रों की प्रस्तुति हुई। इस वर्ष कांग्रेस का केंद्रीय विषय भारतीय भाषाओं में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान है।

प्लेनरी सत्र में विद्वानों के विचार

प्लेनरी सत्र-कर्में प्रख्यात शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों ने भाषा, ज्ञान, विज्ञान और भारतीय बौद्धिक परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय तिवारी ने "छत्तीसगढ़ के लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की प्रगति का मूल्यांकन मानव कल्याण में उनके योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। अनुसंधान की प्राथमिकताएं अक्सर आम जनता की वास्तविक आवश्यकताओं से काफी दूर रहती हैं और ग्रामीणों, आदिवासियों और सुदूर जंगलों में रहने वालों को उनका लाभ बहुत कम मिल पाता है।

पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वंशगोपाल सिंह ने "भारतीय मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में बौद्धिक स्वराज की दिशा : भाषा, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रासंगिकता" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के विकास और भविष्य की दिशा को भाषायी, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक तथा अनुभवजन्य दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है।





प्रो. विकास गुप्ता ने औपनिवेशिक भारत में भाषा अध्ययन की विविध ऐतिहासिक प्रवृत्तियों, भाषाओं के बीच विभाजन तथा भाषा की बदलती प्रकृति विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने Fluidity of Language पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि औपनिवेशिक काल में भाषा का वर्गीकरण और विस्तरण केवल भाषाई प्रक्रिया नहीं था, बल्कि इसका संबंध ज्ञान, सामाजिक संरचना और सत्ता से भी था। उन्होंने मास्टर रामचंद्र जाकुला जैसे विद्वानों के योगदान का उल्लेख किया, जिन्होंने विज्ञान संबंधी ज्ञान को उर्दू में अनूदित करने का प्रयास किया था। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकीय कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर अपना शोध प्रस्तुत किया।

12 सभागारों में 12 समानांतर सत्र

दिन भर अलग-अलग 12 सभागारों में एक साथ 12 समानांतर सत्रों में अलग-अलग विषयों के शोध पत्रों पर चर्चा हुई। इन सत्रों में विज्ञान, शिक्षा, जैविक एवं जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा अन्य समकालीन विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। देश भर के विभिन्न शोध संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लगभग 145 प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया।

आज होगा समापन

दो तकनीकी सत्र होंगे तथा सम्मेलन का समापन समारोह होगा। समापन समारोह की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता प्रेमप्रकाश पांडे करेंगे तथा मुख्य अतिथि दुर्ग आयुक्त सत्यनारायण राठौर होंगे।

खास खबर

भक्ति, तप और श्रद्धा से सराबोर हुआ मां पद्मावती जप अनुष्ठान



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जय आनंद मधुकर रतन भवन, बांधा तालाब, दुर्ग में मां पद्मावती जप अनुष्ठान श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। अनुष्ठान राष्ट्र संत, नेपाल केसरी एवं मानव मिलन संस्थापक पूज्य डॉ. श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में रायपुर ग्रामीण विधायक पुरेनदर मिश्रा एवं लाभचंद बाफना विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सभी घटक दलों की सहभागिता : आयोजन में जैन समाज के विभिन्न घटक दलों के श्रावक-श्राविकाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्म आराधना में सहभागिता निभाई। मां पद्मावती के जप एवं आराधना के माध्यम से श्रद्धालुओं ने सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल की कामना करते हुए आध्यात्मिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समाज के सभी घटकों की सामूहिक सहभागिता धार्मिक एकता, सौहार्द एवं संघ भावना का सुंदर परिचायक रही।

आयंबिल तप की आराधना : इस पावन आयोजन के साथ आयंबिल तप की आराधना का भी विशेष आयोजन जय आनंद मधुकर रतन भवन की भोजनशाला में किया गया। अनेक श्रद्धालुओं ने आयंबिल तप के माध्यम से संयम, त्याग एवं आत्मशुद्धि की साधना की। जैन धर्म में तप को आत्मकल्याण, कर्म निर्जरा एवं आत्मा की निर्मलता का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है।

लकी ड्रॉ में सोने का सिक्का : अनुष्ठान के दौरान एक ग्राम सोने के सिक्के एवं 11 चांदी के सिक्कों का लकी ड्रॉ भी निकाला गया। एक ग्राम सोने के सिक्के का लकी ड्रॉ सौरभ बाफना के नाम निकला। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं में उत्साह एवं आनंद का वातावरण रहा।

चातुर्मास समापन की बेला : अब चातुर्मास के समापन की बेला निकट आ रही है। चातुर्मास के केवल चार दिन शेष हैं तथा आगामी 25 नवंबर को प्रातः विहार होगा। चातुर्मास के अंतिम दिनों में गुरु सानिध्य, धर्म आराधना एवं साधना का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं से अपील की गई।

संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 26 को

दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग द्वारा 26 नवम्बर को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर दुर्ग में संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा है। उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में निजी क्षेत्र के कुल 04 नियोजकों से 10वी, 12वी, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एवं अन्य योग्यताधारी आवेदकों हेतु 195 तकनीकी एवं गैर तकनीकी रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। जिसकी जानकारी रोजगार विभाग के वेबसाईट www.erojgar.cg.gov.in अथवा छग रोजगार एप पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदकों द्वारा जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को रोजगार पंजीयन करवाना अनिवार्य है। जिला स्तरीय रोजगार मेला में सम्मिलित होने के इच्छुक आवेदक रोजगार मेला हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रोजगार मेला हेतु निर्धारित स्थान में अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग में संपर्क कर सकते है। निजी क्षेत्र के नियोजक जो अपने संस्थान में रिक्त पदों को रोजगार मेला के माध्यम से भरना चाहते हैं, वे रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग को अधिसूचित करेंगे छग रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से रिक्तियाँ प्रेषित करने के लिए नियोजकों का पोर्टल पर रोजगार मेला हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए नियोक्ता का जीएसटी क्रमांक एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक होगा।

परामर्श से समाधान : पारिवारिक विवादों में काउंसलिंग की भूमिका पर हुई कार्यशाला

न्यायपालिका-प्रशासन-पुलिस ने किया मंथन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं दुर्ग पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में नवीन कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, दुर्ग में परामर्श से समाधान विषय पर विशेष क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार कुजूर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती सुमन एक्का, सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती कामिनी जायसवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल उपस्थित रहे।

क्या था विषय? : कार्यशाला का विषय पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में परामर्शदाताओं की भूमिका एवं परिवार परामर्श केंद्रों का योगदान रहा। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों के निराकरण में काउंसलिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना तथा न्यायिक व्यवस्था, जिला प्रशासन एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यशाला में परामर्शदाताओं के अनुभव, कार्यप्रणाली एवं व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

कलेक्टर ने दिया प्रेमचंद की कहानी का उदाहरण : कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपने उद्बोधन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी का उल्लेख करते हुए काउंसलिंग की उपयोगिता को सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि कई बार आपसी गलतफहमियां एवं परिस्थितियां पारिवारिक संबंधों में तनाव का कारण बनती हैं। ऐसे मामलों में समय पर संवाद एवं उचित परामर्श मिलने से विवादों को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग का उद्देश्य केवल विवाद समाप्त करना नहीं, बल्कि परिवारों के बीच आपसी विश्वास एवं संबंधों को बनाए रखने में सहयोग करना भी है।

एसएसपी ने बताई पुलिस की संवेदनशील भूमिका : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पारिवारिक विवादों के निराकरण में पुलिस की संवेदनशील एवं उत्तरदायी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परिवार परामर्श केंद्रों के माध्यम से संबंधित पक्षों की समस्याओं को समझकर संवाद एवं आपसी सहमति से समाधान की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने परामर्शदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ऐसे मामलों में धैर्य, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता बताई।

न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार कुजूर ने अपने समापन उद्बोधन में पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए न्यायिक व्यवस्था एवं परामर्श केंद्रों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रभावी परामर्श प्रक्रिया तथा संबंधित संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से विवादों के निराकरण की दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया।

प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती सुमन एक्का ने पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में न्यायिक एवं परामर्श व्यवस्था की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने पारिवारिक संबंधों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उचित मार्गदर्शन एवं आपसी समझ के माध्यम से समाधान की आवश्यकता बताई। सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती कामिनी जायसवाल ने कार्यशाला के विषय एवं उद्देश्य की जानकारी देते हुए परामर्शदाताओं की जिम्मेदारी तथा पारिवारिक विवादों के समाधान में प्रभावी काउंसलिंग के महत्व पर प्रकाश डाला।

पुलिस विभाग के परामर्शदाता द्वारा दुर्ग पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली, परामर्श की प्रक्रिया तथा पारिवारिक विवादों के निराकरण में पुलिस की भूमिका पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

कौन-कौन हुआ शामिल? : कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय तथा कुटुंब न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशगण, कुटुंब न्यायालय के काउंसलर्स, दुर्ग पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यगण शामिल हुए।

पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पारिवारिक विवादों की स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने अथवा विवाद को बढ़ाने के बजाय आपसी संवाद एवं परामर्श का सहारा लें। आवश्यकता पड़ने पर परिवार परामर्श केंद्र की सहायता प्राप्त करें।

नवनिर्मित सामाजिक भवन का मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया लोकार्पण



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के पचरीपारा वार्ड में नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने किया। उन्होंने भवन को क्षेत्रवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि सामाजिक भवन समाज की एकजुटता, आपसी सहयोग और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे।

मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि सामाजिक भवन केवल आयोजनों के लिए एक स्थान नहीं, बल्कि समाज के लोगों के एक साथ जुड़ने, विचारों के आदान-प्रदान और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का केंद्र होते हैं। इस भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहूलियत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दुर्ग विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचनाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि विकास कार्यों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और हर वार्ड में बेहतर सुविधाएं विकसित हों।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि जनसुविधाओं का विस्तार और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास निरंतर जारी रहेगा। जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।



बीएसपी की पुष्पा एम्ब्रोस 7वें आईएसए स्टील कॉन्क्लेव-2026 में जेंडर डायवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई



सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा) श्रीमती पुष्पा एम्ब्रोस को इंडियन स्टील एसोसिएशन द्वारा 17 एवं 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 7वें आईएसए स्टील कॉन्क्लेव-2026 में प्रतिष्ठित जेंडर डायवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इस्पात उद्योग में समावेशिता को बढ़ावा देने तथा महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्टीलः फोर्जिंग द फाउंडेशन ऑफ विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तित्वों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों तथा विभिन्न हितधारकों ने सहभागिता की। कॉन्क्लेव में भारतीय इस्पात उद्योग के भविष्य से जुड़े अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित इस्पात, कार्बन उत्सर्जन में कमी, कच्चे माल की सतत उपलब्धता, आधारभूत संरचना तथा इस्पात क्षेत्र में विकास की उभरती संभावनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

श्रीमती पुष्पा एम्ब्रोस को प्राप्त यह सम्मान इस्पात उद्योग में समावेशी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति उनके व्यावसायिक योगदान एवं प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उनकी यह उपलब्धि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए गौरव का विषय है तथा इस्पात उद्योग में महिला पेशेवरों की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व क्षमता को भी प्रतिबिंबित करती है।

नंदिनियंस मिलन समारोह की तैयारियां हुई तेज आयोजन समिति की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार

22 नवंबर, रविवार को मंगल भवन में सुबह से शाम तक होगा ऐतिहासिक आयोजन



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इस्पात नगरी की लाइमस्टोन माइंस सिटी नंदिनी नगर की पुरानी स्मृतियों और आपसी संबंधों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले नंदिनियंस मिलन समारोह की अंतिम तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सुबह स्थानीय सर्किट हाउस में बैठक हुई। इसमें तमाम प्रमुख नंदिनीवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रविशंकर सिंह की अध्यक्षता एवं राजशेखर तिवारी के संचालन में आयोजित इस बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसका अनुमोदन राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। महिला प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के लिए बिंदु सिंह को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए स्वागत, मंच संचालन, सांस्कृतिक, इंडोर खेल, जलपान एवं भोजन, नगर भ्रमण, सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

प्रतिष्ठित नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष होंगे सम्मानित

बैठक में निर्णय लिया गया कि समारोह में क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षकों, ख्यातिप्राप्त नागरिकों और समाजसेवियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नगर के विकास व सौंदर्यीकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। बैठक में देवेंद्र सिंह परिहार, दिनेश नायर, नंदकिशोर गुप्ता, हरचरण सिंह संधू, इंद्रजीत सिंह ठाकुर, रजिन्दर सिंह, रविन्द्र शुक्ला, तुफैल खान, सुरेंद्र सिंह, स्टालिन, हरीश राठौर, हिमांशु अवस्थी, विजय शर्मा, गजानन कोरे, विरेन्द्र सिंह ठाकुर, अभिषेक सिंह, सतीश फिलीप, जसपाल सिंह, रवि मुदलियार, प्रमोद कुट्टी, दयाशंकर तिवारी, महेंद्र जनबंधु, मोहन सिंह एवं काजल बर्मन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अंत में आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

मृतकों के परिजनों को मिली 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विभिन्न दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु का शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों के लिए कुल 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुभाग दुर्ग के अंतर्गत इंदिरा चौक वैशाली नगर सुपेला भिलाई निवासी स्व. राकेश देवांगन की घटना 09 सितम्बर 2024 को लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के सामने नाली के पानी में डूबने के कारण मृत्यु, महादेव चौक छावनी तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. दुश्वंत कुमार की घटना 12 मार्च 2020 को दरी तालाब में नहाते समय पानी में डूबने से मृत्यु और ग्राम बोरई तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. रामदंड यादव की घटना 18 फरवरी 2026 को ग्राम बोरई के शीतला तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु हुई है। इसी प्रकार अनुविभाग धमधा के अंतर्गत ग्राम करेली तहसील बोरी जिला दुर्ग निवासी स्व. देवांत पटेल की घटना 08 जनवरी 2026 को ग्राम करेली घर के सामने खाली मैदान में खेल रहा था, तभी जहरीले सांप के काटने से मृत्यु हुई है। कलेक्टर सिंह द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुरूप स्व. राकेश देवांगन के पिता परेटन देवांगन, स्व. दुश्वंत कुमार के माता श्रीमती कौशल्या देशमुख, स्व. रामचंद्र यादव की पत्नी, पुत्र, पुत्री श्रीमती रूपा बाई, जितेन्द्र यादव, दीपक यादव, संतोषी यादव और स्व. देवांत पटेल के पिता एवं माता तरूण कुमार, श्रीमती भारती पटेल क्रमशः 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

भिलाई-चरोदा नगर निगम चुनाव 2026 : कांग्रेस ने 40 वार्डों के लिए 80 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-चरोदा

आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2026 के लिए जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) ने नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के सभी 40 वार्डों में वार्डवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने क्रमांक-201/2026/नगरीय निकाय चुनाव, 19 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं एवं दावेदारों से आवेदन प्राप्त करने तथा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए यह नियुक्ति की गई है।

क्या करेंगे पर्यवेक्षक?

नियुक्त पर्यवेक्षक अपने निर्धारित वार्डों में कांग्रेसजनों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करेंगे। बैठक की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त सभी आवेदनों एवं दावेदारों के नामों की सूची संबंधित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निर्धारित समय-सीमा में सौंपना सुनिश्चित करेंगे। सभी नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ संपन्न करें तथा निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें।

प्रत्येक वार्ड में 2-2 पर्यवेक्षक

भिलाई-चरोदा निगम के वार्ड 01 इंदिरानगर हथखोज से लेकर वार्ड 40 गनियारी तक प्रत्येक वार्ड में 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कुल 80 पर्यवेक्षकों की सूची आदेश के साथ संलग्न की गई है। आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एवं प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैन्दू को सादर सूचनार्थ भेजी गई है।

!! न्यायालय तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग !!

-:: इश्तहार ::-

रा.प्र.क्र. ब-121 वर्ष 2026-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हिरोज पिता स्व. सालिक राम निवासी सुपेला भिलाई द्वारा आवेदक के बडे पिता पतिराम पिता मड्डू की मृत्यु हो जाने के कारण वारीसान प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः उक्त संबंध में पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 27.11.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05.11.2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला स्थान

राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026' में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया 'समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।



पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।

स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 के अंतर्गत डिजिटल अर्डॉप्शन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

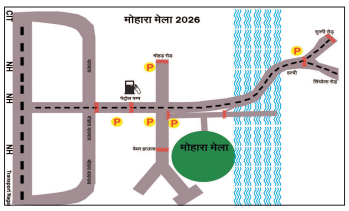
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अर्डॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी।

इस अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के अध्यक्ष राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से शहरी आजीविका संवर्धन, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन और छोटे व्यवसायियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

खास खबर

मोहारा मेला के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 23 से 25 तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित



नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

मोहारा मेला में बड़ी संख्या में दर्शकों एवं आम नागरिकों के सम्मिलित होने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस राजनांदगांव द्वारा सुगम यातायात संचालन एवं आम जनता की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी 23 नवंबर 2026 को दोपहर 03 बजे से 25 नवंबर 2026 को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी।

एडवाइजरी के प्रमुख बिंदु

भारी एवं मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित और मोहारा क्षेत्र में उक्त अवधि में भारी एवं मध्यम वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

बालोद-धमतरी से राजनांदगांव आने वाले वाहन और बालोद-धमतरी की ओर से राजनांदगांव आने वाली भारी व चार पहिया वाहन सुरगी से डायवर्सन होकर मोखला, भरेगांव, खुटेरी से नेशनल हाईवे की ओर से निकलकर राजनांदगांव आएंगी।

दल्लीराजहरा से आने वाले वाहन और दल्लीराजहरा की ओर से आने वाली वाहन जेवरतला से डायवर्सन होकर नांदिया, डोगरगांव से राजनांदगांव की ओर आएंगी। चारपहिया वाहन सिंघोला, करमतरा, मोखला, कोटरासरार होकर जंगलपुर से राजनांदगांव आएंगी।

राजनांदगांव से बाहर जाने वाले वाहन और राजनांदगांव से धमतरी-बालोद जाने वाले वाहन टोलप्लाजा खुटेरी, मोखला, सुरगी होकर धमतरी-बालोद की ओर जाएंगे। तथा दल्लीराजहरा की ओर जाने वाली भारी वाहन डोगरगांव-नांदिया से जेवरतला होकर दल्लीराजहरा जाएंगी। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मेला अवधि में निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

हिस्ट्रीशीटर का हाईवोल्टेज ड्रामा: लोहे की रॉड लेकर सड़क पर मचाया आतंक, खड़ी कार-बाइक में की तोड़फोड़

बिलासपुर। शहर के चांदनी चौक इलाके में एक हिस्ट्रीशीटर ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। हाथ में लोहे की रॉड लेकर निकले आरोपी ने राहगीरों को दौड़ाया और सड़क पर खड़ी कार व बाइक को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस के सामने भी नहीं रुका उत्पात : बताया जा रहा है कि हंगामे की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन आरोपी का व्यवहार ऐसा था कि वह पुलिसकर्मियों के सामने ही गाली-गलौज और हुज्जत करने लगा। पुलिसकर्मी उसका नाम-पता दर्ज कर वहां से लौट गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी आरोपी का हंगामा जारी रहा।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, एसएसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश : इस पूरी घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। एसएसपी के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर भूपेन्द्र दुबे उर्फ पंडा को हिरासत में ले लिया है।

नक्सलवाद के साये से समृद्धि के उजाले तक, भारत मंडपम में दिखा नए छत्तीसगढ़ का आया नया चेहरा

मुख्यमंत्री साय बोले, राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / ०००००

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं के रंगों से सराबोर रही। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों और लोक संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह ने राष्ट्रीय राजधानी में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और जीवंत लोक कलाओं की मनमोहक झलक प्रस्तुत की।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, उद्योग और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की व्यापक संभावनाओं वाला राज्य है। प्रदेश में इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, एल्युमिनियम, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के माध्यम से निवेश, रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यपाल ने देश-विदेश से आए उद्योगपतियों और निवेशकों से छत्तीसगढ़ की संभावनाओं का लाभ उठाने तथा प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की वास्तविक शक्ति यहां के मेहनतकश किसान, प्रतिभाशाली युवा, महिलाएं और कुशल शिल्पकार हैं। युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन स्थलों में आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से समृद्ध, औद्योगिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली और सामाजिक रूप से समरस राज्य बनाया जा सकता है।



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब बदल रही है। जिस बस्तर और छत्तीसगढ़ की चर्चा कभी नक्सलवाद और चुनौतियों के संदर्भ में होती थी, आज वही प्रदेश अपनी समृद्ध जनजातीय विरासत, जीवंत लोक संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास की नई संभावनाओं के साथ देश-दुनिया के सामने नई पहचान बना रहा है। भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नजर आया छत्तीसगढ़ का स्वरूप इसी बदलते दौर की कहानी बयां कर रहा है। यहां परंपरा और आधुनिकता, विरासत और विकास तथा स्थानीय हुनर और आर्थिक संभावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है, जब वे इतनी बड़ी संख्या में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, जनजातीय विरासत और विकास की अनूठी झलक देखने को मिल रही है, जो प्रदेश की बदलती तस्वीर और नई पहचान को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और अनूठी लोक परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रदेश की लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसे लोक कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है। गौर, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा जैसे लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन देश-विदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्य सभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज विशेष रूप से उपस्थित थे।

भारत मंडपम के एम्फी थिएटर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण प्रदेश के लोक कलाकारों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। मांदर, ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज के बीच कलाकारों की ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण में उत्सव का रंग भर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौर नृत्य के माध्यम से बस्तर की जनजातीय परंपराओं की झलक देखने को मिली, वहीं गौरा-गौरी नृत्य ने प्रदेश की लोक आस्था और परंपराओं से दर्शकों को परिचित कराया। भोजली नृत्य में छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और प्रकृति के प्रति लोक आस्था की अभिव्यक्ति हुई। पारंपरिक वेशभूषा और विशिष्ट नृत्य शैली के साथ प्रस्तुत राउत नाचा ने प्रदेश की लोक परंपराओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सैन, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वदेव कुमार, छत्तीसगढ़ की आवासीय आयुक्त श्रीमती श्रुति सिंह तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उप संचालक पंकज कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर वहां प्रदर्शित उत्पादों, हस्तशिल्प कलाकृतियों और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बस्तर की पारंपरिक बेलमेटल कला, चांपा के कोसा सिल्क, जनजातीय आभूषणों, हथकरघा वस्त्रों तथा वनोपज आधारित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट उत्पादों की भी जानकारी ली तथा छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किए जाने की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पवेलियन में चित्रकोट जलप्रपात के 3डी वर्चुअल रियलिटी अनुभव की विशेष सराहना की। इस तकनीक के माध्यम से आगंतुकों को बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता का आभासी अनुभव कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करना पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। इससे देश-विदेश के आगंतुक छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं से परिचित हो रहे हैं।

माओवाद के खात्मे के बाद नेशनल पार्क क्षेत्र में नवीन थाना पीलूर का शुभारंभ, बीजापुर का 24वां थाना

बीजापुर। माओवाद के खात्मे के बाद अब तक दुर्गम रहे नेशनल पार्क क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुंच बढ़ाने और ग्रामीणों को सुरक्षा व सुगम न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पीलूर में स्वीकृत नवीन थाना का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा के हाथों किया गया। थाना पीलूर जिला बीजापुर का 24वाँ थाना है। इस थाना क्षेत्र में कुल 15 ग्राम शामिल होंगे। उप निरीक्षक हनीफ खान को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवीन थाने के खुलने से क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा।

साथ ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, जिला पंचायत सदस्य तिमेड़ श्रीमती कविता कुड़ेम, जनपद पंचायत अध्यक्ष भोपालपटनम् श्रीमती सरिता कोरसा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भोपालपटनम् गणपत नीलम, जनपद सदस्य दिनेश मड़े, सरपंच बड़े काकलेर, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा, उप महानिरीक्षक केरिपु बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता, कमांडेंट 214 वाहिनी केरिपु मनीश शर्मा, कमांडेंट 22 वाहिनी केरिपु रणदीप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर इन्द्रावती टाइगर रिजर्व सुदेश सुरवाड़े, अति. पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार मीणा, एसडीओपी भोपालपटनम् सिद्धार्थ चौहान, एसडीओपी फरसेगढ़ अमन लखीसरानी उपस्थित रहे। इनके साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

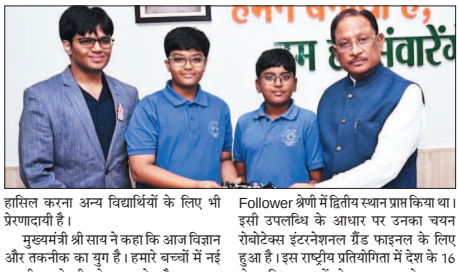


बधाई रोबोटिक्स की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए रायपुर के पराक्रम सिन्हा और मोहम्मद गौस अंसारी का चयन

छग के दो होनहार विद्यार्थी दक्षिण कोरिया में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के दो होनहार विद्यार्थी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। रायपुर के वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा सातवीं के विद्यार्थी पराक्रम सिन्हा और मोहम्मद गौस अंसारी का चयन दक्षिण कोरिया में 28 एवं 29 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली रोबोटेक्स इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों विद्यार्थी इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से दोनों विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले तो वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में रोबोटिक्स जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज विज्ञान और तकनीक का युग है। हमारे बच्चों में नई तकनीक को सीखने, समझने और नवाचार करने की रुचि बढ़ रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर मिलें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों विद्यार्थी दक्षिण कोरिया में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हासिल किया द्वितीय स्थान : उल्लेखनीय है कि पराक्रम सिन्हा और मोहम्मद गौस अंसारी ने नेशनल चैंपियनशिप 2026 की LEGO Line Follower श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसी उपलब्धि के आधार पर उनका चयन रोबोटेक्स इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल के लिए हुआ है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 16 से अधिक राज्यों के 7 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता की नौ अलग-अलग श्रेणियों में 500 से अधिक रोबोट्स के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी तकनीकी दक्षता और नवाचार क्षमता का प्रदर्शन किया। विभिन्न श्रेणियों से चयनित 36 विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है।

LEGO Line Follower श्रेणी में विद्यार्थियों को ऐसा रोबोट तैयार करना होता है, जो निर्धारित ट्रैक पर बनी लाइन को पहचानकर उसके अनुसार आगे बढ़ सके। इसके लिए प्रोग्रामिंग, तार्किक सोच, तकनीकी समझ और समस्या समाधान की क्षमता आवश्यक होती है।

शिक्षकों और तकनीकी मार्गदर्शकों का महत्वपूर्ण योगदान : दोनों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि में उनके अभिभावकों, शिक्षकों और तकनीकी मार्गदर्शकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान वैदिक इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती नीलम चौधरी, रोबोनाइट रोबोटिक्स के सीईओ एवं चीफ मेंटर रवि सिन्हा, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रीना सिन्हा तथा टीम कोच शौर्य सिन्हा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों के साथ उनके शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में शिक्षकों और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रायपुर के इन दोनों विद्यार्थियों की उपलब्धि ने यह साबित किया है कि लगन, परिश्रम और उचित मार्गदर्शन से कम उम्र में भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी प्रदेश के अन्य विद्यार्थियों को भी विज्ञान, रोबोटिक्स और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल द्वारा दिवाली मिलन व संयुक्त कार्यकारिणी की हुई बैठक



नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल द्वारा वृंदावन हॉल में संयुक्त कार्यकारिणी बैठक एवं दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वामा परिवार की लगभग 50 सदस्य उपस्थित रहीं और सभी ने दीपावली की खुशियां उत्साह एवं उमंग के साथ साझा कीं।

कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों की थीम रखी गई। बेस्ट ड्रेसअप प्रतियोगिता के अंतर्गत आकर्षक रैंप शो आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों ने अपनी सुंदर पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन किया। बेस्ट ड्रेसअप में प्रथम स्थान रूपा सिंह एवं द्वितीय स्थान हर्षल छाजेड़, पिंकी सोनकर एवं रुपाली धारा ने प्राप्त किया।

वहीं, दीपावली के अवसर पर सदस्यों द्वारा अपने-अपने घरों में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी की गई। इसमें हर्षल छाजेड़ एवं पूजा चंडालिया विजेता रहीं। कार्यक्रम में हौजी सहित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का सभी ने भरपूर आनंद लिया। इसके पश्चात संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं आगामी गतिविधियों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में चेयरमैन पीपीपी जेएफआर राजेश अग्रवाल जी, फाउंडर प्रेसिडेंट जेसीआई सीनेटर लीना वाहेर, प्रेसिडेंट जेसी डॉ. धृति वैभव शर्मा, आईपीपी जेसी आस्था वाघना, सचिव जेसी प्रीति अग्रवाल, आगामी चैप्टर इंचार्ज एचजीएफ दीया मूलचंदानी, इलेक्ट प्रेसिडेंट जेसी गुंजन गोलछा एवं इलेक्ट सचिव जेसी श्रावणी मुकादम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा भाविका रोहरा ने बनाई। यह आयोजन आपसी प्रेम, सौहार्द एवं एकजुटता का सुंदर उदाहरण बना और सभी के लिए यादगार रहा।

संपादकीय

क्या नहीं किया और क्या करना है, बता तो दिया

परिवार के मुखिया को परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना पड़ता है ।सभी के सुख दुख का उसे पता रहता है जब मौका आता है तो उसके सुख दुख की बात भी वह करता है,साथ ही वह यह भी बताता रहता है कि हम सब परिवार के लोग हैं तो हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए ।मैं परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं तो परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वह भी परिवार के लिए जो जरूरी हैं, वह तो करें ।पीएम मोदी के लिए पूरा देश परिवार है,देश के उद्योगपति उनके परिवार के हिस्सा हैं तो उद्योगपतियों के कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारी भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। देश का लक्ष्य विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाने में जितनी अहम भूमिका उद्योगपतियों की है, उतनी ही अहम भूमिका कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी है ।पीएम मोदी तो देश की बेहतरी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं,सबको खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करते हैं ।सभी को याद भी दिलाते हैं कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए और दूसरों को देश के लिए क्या करना था और क्या हीं किया है।

दिल्ली में FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को याद दिलाया सरकार ने आपको टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी, कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचाने के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया, GST में सुधार किए, कारोबार करना आसान बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? क्या उनकी सैलरी बढ़ाई? क्या आपने अपनी कंपनियों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए? आखिर सरकार की ओर से दी जा रही राहत का फायदा आपके यहां काम करने वाले कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा?" प्रधानमंत्री का सवाल था कि जब सरकार ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी राहत दी, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई? क्या युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा की गईं? उनका जवाब भी उन्होंने खुद दिया- नहीं! कंपनियों का रवैया यही है कि मोदी जी, आप अपना काम कीजिए, हम बाद में देखेंगे।

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर महीने अपनी मेहनत, समय और प्रतिभा से कंपनियों की तरक्की में योगदान देते हैं। किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मालिकों, निवेशकों या प्रबंधन की उपलब्धि नहीं होती। उसके पीछे उन कर्मचारियों की मेहनत भी होती है, जो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़कर काम करते हैं, लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव झेलते हैं और कंपनी के कारोबार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब सरकार की नीतियों से उद्योग जगत को राहत मिलती है, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना चाहिए ।मोदी ने उद्योगपतियों को यह भी याद दिलाया कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले जहां रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है। GST सुधारों के कारण अनेक उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना मजबूत हुई है। लेकिन इस आर्थिक गतिविधि का लाभ केवल कंपनियों के खातों और मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

पीएम मोदी का छवि राहुल गांधी व कांग्रेस ने उद्योगपतियों के हित में काम करने वाले पीएम की बना रखी थी, वह आए दिन बयान देकर देश के कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बताने का प्रयास करते थे कि देखो पीएम मोदी उद्योगपतियों के कितना कुछ करते हैं,कर्मचारियों के हित में कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं तो पीएम मोदी ने फिक्की के 100 वें वार्षिक सम्मेलन में वह काम किया । उन्होंने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों के लिए जो कुछ किया है, उसका मकसद था कि वह कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को राहत दी थी, पैसा बचेगा,मुनाफा बढ़ेगा तो वह नए कर्मचारी भर्ती करेंगे,पुराने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया है यह तो पीएम मोदी ने याद दिलाया और यह भी याद दिलाया कि ऐसा करना क्यों जरूरी है ।ऐसा करने पर ही देश मे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है ।इसका देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा ।देश चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

प्रधानमंत्री का संदेश केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता घटाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। उनका कहना था कि 140 करोड़ लोगों का विशाल घरेलू बाजार उद्योगों के लिए सुविधा जरूर है, लेकिन इसे गुणवत्ता से समझौता करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय उपभोक्ताओं को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिलने चाहिए। साथ ही फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने अगले 20 वर्षों का लक्ष्य रखते हुए हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में 'देश पहले' को आधार बनाने की अपील की। लेकिन इस पूरे संबोधन का सबसे सीधा संदेश देश के नौकरीपेशा वर्ग के लिए था कि आर्थिक विकास का फायदा उस कर्मचारी तक भी पहुंचना चाहिए, जिसकी मेहनत से कंपनी का विकास संभव होता है। देखा जाये तो कंपनियों के लिए अब सवाल सिर्फ कारोबार बढ़ाने और मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि उस विकास में अपने कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का भी है। आखिर जब कंपनी आगे बढ़ती है फायदा कमाती है तो उसके कर्मचारी को भी उसका फायदा मिलना चाहिए।

बिहार राजग सरकार का एक साल

भूमंडलीकृत दुनिया में नई पहचान गढ़ता बिहार

प्रो. संजय द्विवेदी



बिहार की ऐतिहासिक पहचान ज्ञान, संस्कृति और लोकतांत्रिक चेतना की रही है, लेकिन 21वीं सदी के भूमंडलीकृत परिदृश्य में राज्य के सामने अपनी औद्योगिक और आर्थिक पहचान को नये सिरे से गढ़ने की एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों मौजूद हैं। हाल ही में पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के 'संवाद' सभागार में बिहार फाउंडेशन की पुनर्गठित वेबसाइट और 'बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027' पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही 'बिहार है तैयार' अभियान का आगाज हुआ है, जो राज्य के प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव को रेखांकित करता है। यह पहल केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नहीं है, बल्कि देश-विदेश में बसे करोड़ों बिहारियों को अपनी मातृभूमि के आर्थिक पुनरुत्थान से जोड़ने और राज्य को पूर्वी भारत के एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास है।

हालांकि, यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या केवल डिजिटल पोर्टलों और नये अभियानों के सहारे दशकों से चले आ रहे औद्योगिक पिछड़ेपन के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है? अतीत में भी कई बार 'निवेश सम्मेलनों' और बड़े-बड़े वादों की झड़ी लगी है, लेकिन धरातल पर उनका असर सीमित ही रहा है। ऐसे में, यदि इस बार वास्तव में बदलाव लाना है, तो सरकार को सिर्फ इरादों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत पर काम करना होगा।

प्रवासी बिहारी समाज आज संपूर्ण विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा और कॉर्पोरेट नेतृत्व के शीर्ष स्तरों पर स्थापित है। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित 55 अध्यायों (31 अंतरराष्ट्रीय और 24 राष्ट्रीय) का नेटवर्क इस बात का सशक्त प्रमाण है कि राज्य के पास एक विशाल वैश्वीकृत शक्ति मौजूद है।

सरकार द्वारा प्रवासियों को केवल भावनात्मक रिश्ते तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य का वास्तविक 'ब्रांड एंबेसडर' घोषित करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। जब विदेश में बैठा कोई बिहारी पेशेवर अपनी कर्मभूमि पर बिहार के सकारात्मक बदलावों की वकालत करता है, तो वैश्विक निवेशकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना सुदृढ़ होती है। लेकिन प्रवासी समुदाय अक्सर यह शिकायत करता है कि कागजी घोषणाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक चौड़ी खाई आज भी मौजूद है। बिहार फाउंडेशन की नई वेबसाइट इस संवाद को कितना पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित बना पाती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासनिक लालफीताशाही और नौकरशाही के अड़ंगे इसमें कितनी जल्दी दूर किये जाते हैं।

औद्योगिक क्रांति का मार्ग केवल संभावनाओं की बात करने से नहीं, बल्कि ठोस बुनियादी ढांचे को पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारने से प्रशस्त होता है। फरवरी, 2027 में प्रस्तावित 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' सम्मेलन को लेकर बड़े दावे किये जा रहे हैं। राज्य को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की बात कही जा रही है, जो उत्साहजनक तो है, लेकिन अनुभव यह बताता है कि 'एमओयू' के आंकड़े अक्सर जमीनी निवेश में पूरी तरह तब्दील नहीं हो पाते।

निवेशकों की सबसे प्राथमिक आवश्यकता-स्पष्ट और विवाद-मुक्त भूमि-को पूरा करने के लिए फरवरी 2027 तक 20,000 एकड़ भूमि का एक विशाल लैंड बैंक तैयार करने का दावा है, जिसमें से लगभग 13,500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 1,670 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही 'गया मैन्युफैक्चरिंग सिटी' (BIMCGL) परियोजना 16,500 करोड़ रुपये के निवेश और 1.1 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने की क्षमता रखती है। बावजूद इसके, भूमि अधिग्रहण से जुड़े स्थानीय विवाद, मुआवजे के पेंच और अदालती मुकदमे अक्सर ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की गति को धीमा कर देते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भूमि बैंक सचमुच विवाद-मुक्त हों, अन्यथा निवेशक वादों के जाल में फंसकर दूसरे राज्यों का रुख करने में देर नहीं लगाएंगे।

औद्योगिक प्रगति का पहिया केवल कारखानों के निर्माण से नहीं घूमता, बल्कि इसके लिए एक सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स और नीतिगत तंत्र की आवश्यकता होती है। बिहटा में ड्राई पोर्ट की स्थापना ने बिहार को सीधे समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही, पटना, गयाजी और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों से अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों के विस्तार के प्रयास औद्योगिक प्रतिनिधियों की आवाजाही को सुगम बनाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा नदियों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु लाई गई 'गाद नीति' भी बुनियादी ढांचा सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। सिंगल-विंडो डिजिटल पोर्टल के जरिए निवेशकों को सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना सराहनीय है, बशर्ते यह पोर्टल महज एक और खानापूर्ति बनकर न रह जाए और वास्तव में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के स्तर को कम कर सके। बिहार में कानून-व्यवस्था और नीतिगत स्थिरता को लेकर उद्योग जगत की जो पुरानी हिचकिचाहट रही है, उसे दूर करने के लिए केवल पोर्टल नहीं, बल्कि सख्त प्रशासनिक इच्छाशक्ति की दरकार है।

बिहार का सबसे सशक्त संसाधन उसका मेधावी मानव बल है। लंबे समय से कुशल श्रम और प्रतिभा का पलायन राज्य के सामने एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती रहा है, लेकिन वर्तमान रणनीति इस 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन सकुर्लेशन' और स्थानीय रोजगार में बदलने का दावा करती है।

सरकार का यह तर्क अपनी जगह सही है कि यदि उद्योगों को विशिष्ट कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, तो बिहार सरकार उनके साथ स्किलिंग पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि राज्य के भीतर उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता आज भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। जब तक स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शी रोजगार के अवसर नहीं सुधरते, तब तक केवल कागजी कौशल विकास योजनाओं से युवाओं का भला होना मुश्किल है। बिहार फाउंडेशन के वैश्विक अध्यायों के माध्यम से प्रतिभाओं को जोड़ने की बात तो अच्छी है, पर क्या सामान्य और गरीब परिवारों के स्थानीय युवाओं को भी इन अवसरों तक सीधी पहुंच मिल पाएगी, या यह मंच भी केवल गिने-चुने लोगों तक सीमित रह जाएगा?

बिहार फाउंडेशन की नई वेबसाइट और 'बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027' पोर्टल का शुभारंभ राज्य के आत्मविश्वास को जरूर दर्शाता है। प्रवासी बिहारियों की विशेषज्ञता, भूमि बैंक, सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स और युवाओं के कौशल संवर्धन का यह ढांचा तभी सार्थक साबित होगा जब सरकार अपनी योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और धरातलीय परिणामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। जब तक नीतियों के क्रियान्वयन में राजनीतिक और प्रशासनिक दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक 'बिहार है तैयार' का नारा कागजी घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिहार के विकास के लिए अब दावों से ज्यादा कड़े और ईमानदार सुधारों की जरूरत है।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान-आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक हैं।)



चमकती वंदे भारत की आड़ में सिसकता आम यात्री और सत्ता की जवाबदेही

अशोक भाटिया

भारतीय रेल केवल लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाला एक यातायात तंत्र भर नहीं है, बल्कि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले इस विशाल देश की धड़कन, एकता और सामाजिक ताने-बाने की सबसे मजबूत डोर है। उत्तर भारत के किसी छोटे से कस्बे से रोजगार की तलाश में दक्षिण भारत के किसी औद्योगिक शहर की ओर जाने वाला श्रमिक हो, या फिर अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा और किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने निकला मध्यमवर्गीय नागरिक—भारतीय रेल सदियों से हर वर्ग की आकांक्षाओं को ढोती रही है। किंतु आज भारतीय रेलवे एक ऐसे विरोधाभासी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ हाई-स्पीड और विश्वस्तरीय आधुनिकता की चमक-दमक है, तो दूसरी तरफ आम यात्री के लिए बुनियादी मानवीय गरिमा और सुरक्षित सफर का गहरा संकट। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और स्टेशनों के कायाकल्प को अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में प्रचारित किया है, उसने रेल के असल स्वरूप और उसकी प्राथमिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर चमचमाती वातानुकूलित बोगियों को हरी झंडी दिखाने के भव्य सरकारी आयोजन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं स्टेशनों के दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी साधारण ट्रेनों के जनरल और स्लीपर डिब्बों में भेड़-बकरियों की तरह ठुंसे यात्रियों की तस्वीरें सत्ता की संवेदनहीनता और नीतिगत प्राथमिकताओं की पोल खोलती हैं।



आज देश के किसी भी बड़े रेलवे जंक्शन—चाहे वह उत्तर में नई दिल्ली, पटना, लखनऊ और प्रयागराज हो या दक्षिण में चेन्नई, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और कोच्चि—पर जाकर देखा जाए तो दो अलग-अलग भारत एक साथ यात्रा करते नजर आते हैं। एक भारत वह है जो ऊंचे किराए चुकाकर एयरपोर्ट जैसे दिखने वाले स्टेशनों के लाउंज में बैठता है और स्वचालित दरवाजों वाली आधुनिक ट्रेनों में आरामदायक सफर करता है। दूसरा भारत वह है जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से टिकट खरीदने के बावजूद ट्रेन के शौचालयों के पास बैठकर या दरवाजों पर लटककर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने को अभिशप्त है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में तो यह स्थिति किसी मानवीय त्रासदी से कम नहीं होती, लेकिन अब सामान्य दिनों में भी साधारण ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। विडंबना यह है कि जब सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से इस अमानवीय भीड़ के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय इसे यात्रियों की अनुशासनहीनता या बढ़ती आबादी का स्वाभाविक परिणाम बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह तर्क इस कड़वे सच को छिपाने की राजनीतिक कोशिश है कि पिछले एक दशक में प्रीमियम और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों की संख्या तो तेजी से बढ़ाई गई, लेकिन आम आदमी की सवारी कहे जाने वाले अनारक्षित यानी जनरल और नॉन-एसी स्लीपर डिब्बों की संख्या में सुनियोजित तरीके से कटौती की गई।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान ने भारतीय रेल को जनसेवा के माध्यम के बजाय अपने चुनावी प्रचार और छवि निर्माण के सबसे बड़े उपकरण में बदल दिया है। जिस राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, वहां नई ट्रेनों के लोकार्पण और स्टेशनों के शिलान्यास की झड़ी लग जाती है। इन आयोजनों को जिस भव्यता के साथ टेलीविजन और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है, उससे ऐसा आभास होता है मानो देश की रेल व्यवस्था किसी स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन प्रचार के इस चकाचौंध भरे पर्दे के पीछे की जमीनी हकीकत बेहद भयावह है। जब किसी रेल दुर्घटना में दर्जनों निर्दोष नागरिकों की जान जाती है या सिग्नल प्रणाली की विफलता से पटरियों पर खून बहता है, तब न तो कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है और न ही शीर्ष स्तर पर कोई जवाबदेही तय होती है। पुराने दौर में रेल हादसों के बाद मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने की जो लोकतांत्रिक परंपरा थी, उसे आज के आक्रामक पीआर (जनसंपर्क) तंत्र ने पूरी तरह दफन कर दिया है। संकट के समय सुधार करने के बजाय सरकारी मशीनरी का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बदहाली के वीडियो को कैसे दबाया जाए और कहानी को कैसे मोड़ा जाए।

इसके साथ ही रेल बजट और परियोजनाओं के आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगातार गहराते जा रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में जहां प्रवासी मजदूरों और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्रियों को तीन-तीन दिन तक बिना बुनियादी सुविधाओं के किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है, वहीं दक्षिण के कई राज्यों का यह आरोप भी राजनीतिक तूल पकड़ रहा है कि केंद्र सरकार की अधिकांश महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाएं और बजटीय आवंटन उन्हीं राज्यों पर केंद्रित हैं जहां सत्तारूढ़ दल को सीधा चुनावी लाभ दिखता है। संघीय ढांचे में बुनियादी ढांचे का विकास राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। जब नीति निर्माण का सारा ध्यान प्रीमियम मतदाताओं और चुनावी समीकरणों पर केंद्रित हो जाता है, तो देश का आम नागरिक खुद को अपने ही देश की सार्वजनिक व्यवस्था में दोयम दर्जे का महसूस करने लगता है।

इस पूरे परिदृश्य का एक और अत्यंत चिंताजनक पहलू रेल सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। आधुनिकता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाएं, पटरियों के रखरखाव में लापरवाही और कवच जैसी सुरक्षा प्रणालियों के धीमे विस्तार ने यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे की नींव को मजबूत किए बिना केवल ऊपरी सजावट पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे के भीतर लाखों की संख्या में सुरक्षा और तकनीकी से जुड़े पद वर्षों से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नई भर्तियां करने के बजाय ठेका प्रथा और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ, वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनों को समय पर चलाने की होड़ में साधारण पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को घंटों तक आउटर सिग्नल पर खड़ा रखा जाता है। एक दिहाड़ी मजदूर या छोटे व्यापारी के लिए समय की कीमत किसी कॉरपोरेट अधिकारी से कम नहीं होती, लेकिन सत्ता की इस नई कार्यसंस्कृति ने यह मान लिया है कि कम किराया देने वाले गरीब यात्री के समय, उसकी सुविधा और उसके धैर्य की कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलने वाली किराया रियायतों को समाप्त करने का फैसला भी इसी संवेदनहीन और मुनाफाखोर सोच का हिस्सा है, जिससे लाखों बुजुर्गों के लिए अपनों से मिलना या तीर्थयात्रा करना कठिन हो गया है।

रेलवे के निजीकरण और व्यावसायीकरण की सरकारी नीतियां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सीधा प्रहार हैं। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब एक लोकतांत्रिक सरकार जनसेवा के मूल सिद्धांत को पूरी तरह मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ा देती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं बचता। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए नहीं बनी कि उसने मुनाफा कमाया, बल्कि इसलिए बनी कि उसने देश के सबसे गरीब नागरिक को भी सस्ती और सुलभ गतिशीलता प्रदान की। आज सत्ता पक्ष जिस तरह से आम आदमी की जेब पर बोझ डालकर और उसकी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करके केवल कुछ चुनिंदा हाई-स्पीड ट्रेनों के जरिए विकसित भारत की तस्वीर पेश कर रहा है, वह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आत्ममुग्धता और प्रचार की राजनीति से बाहर निकले और भारतीय रेलवे की प्राथमिकताओं को जमीनी हकीकत के अनुरूप दुरुस्त करे। देश को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की रफ्तार जरूर चाहिए, लेकिन यह रफ्तार साधारण ट्रेनों की पटरियां उखाड़कर या जनरल डिब्बों की बलि देकर हासिल नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि वह हर लंबी दूरी की ट्रेन में अनारक्षित और स्लीपर डिब्बों की पर्याप्त संख्या तत्काल बहाल करे, नई जनसाधारण ट्रेनों का परिचालन बढ़ाए और रेलवे के रिक्त सुरक्षा पदों को अविलंब भरे। स्टेशनों के बाहरी सौंदर्यीकरण के साथ-साथ साधारण प्लेटफॉर्मों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सुरक्षित प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करना सत्ता का संवैधानिक दायित्व है। अंततः, किसी भी सरकार की सफलता उसके चमकते हुए विज्ञापनों या तेज रफ्तार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की तस्वीरों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस देश का सबसे साधारण नागरिक अपनी यात्रा के दौरान कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। जब तक जनरल डिब्बे में सफर करने वाले आम भारतीय के चेहरे पर सुकून और उसकी यात्रा में गरिमा नहीं लौटती, तब तक सत्ता के तमाम दावे महज एक राजनीतिक छलावा ही माने जाएंगे।

लौह महिला इंदिरा गांधी : दृढ़ नेतृत्व, अदम्य साहस और सशक्त भारत की प्रेरक गाथा

सत्यभूषण शर्मा

भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके निर्णय, संघर्ष, उपलब्धियाँ और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए विमर्श का विषय बन जाते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ऐसा ही एक व्यक्तित्व थीं। उनका जीवन संघर्ष, संकल्प, साहस, राजनीतिक दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति का ऐसा अध्याय है, जिसने भारतीय राजनीति को नई पहचान दी। 19 नवंबर को उनकी जयंती केवल एक राजनीतिक हस्ती को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, महिला नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की यात्रा का मूल्यांकन करने का भी दिन है।

स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से प्रधानमंत्री पद तक

19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में जन्मी इंदिरा गांधी का बचपन स्वतंत्रता आंदोलन के वातावरण में बीता। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और दादा पंडित मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में शामिल थे। घर का वातावरण राष्ट्रीय चेतना, त्याग और राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत था। बचपन से ही उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष को निकट से देखा और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का अनुभव किया।

उनके व्यक्तित्व का निर्माण केवल पारिवारिक राजनीतिक विरासत से नहीं हुआ, बल्कि जीवन के संघर्षों, अनुभवों और चुनौतियों ने भी उन्हें एक दृढ़ निश्चयी नेता बनाया। 1966 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से जूझ रही थीं। उस समय उनके नेतृत्व और निर्णय क्षमता की कड़ी परीक्षा हुई।

लौह महिला की पहचान और ऐतिहासिक निर्णय

इंदिरा गांधी को विश्व राजनीति में लौह महिला के रूप में पहचान मिली। इसका आधार उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का साहस था। वर्ष 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध उनके राजनीतिक जीवन का एक ऐतिहासिक पड़ाव बना। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ और भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसी वर्ष उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की दिशा में कदम बढ़ाया। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसने विश्व समुदाय को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और सामरिक आत्मनिर्भरता का परिचय दिया।

उनके कार्यकाल में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व रियासतों के प्रिवी पर्स की समाप्ति तथा कृषि और खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने जैसी महत्वपूर्ण नीतियाँ अपनाई गईं। हरित क्रांति के विस्तार ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया। इन कदमों ने देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला।

महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक मिसाल

उस दौर में जब विश्व के अनेक देशों में महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के अवसर सीमित रूप से प्राप्त थे, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। उन्होंने यह स्थापित किया कि नेतृत्व की क्षमता का निर्धारण लिंग से नहीं, बल्कि दृष्टि, योग्यता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता से होता है।

उनका राजनीतिक जीवन भारतीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना। उन्होंने महिलाओं के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि सामाजिक सीमाओं और पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देकर भी सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुँचा जा सकता है।

आज जब भारत महिला सशक्तीकरण, समान अवसर और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी की बात करता है, तब इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक योगदान भी स्मरणीय हो उठता है।



उपलब्धियों के साथ लोकतांत्रिक चुनौतियों का मूल्यांकन

किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन केवल उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके विवादास्पद निर्णयों और उनके परिणामों के आधार पर भी होना चाहिए। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादास्पद अध्याय 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गंभीर प्रतिबंध लगे। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुईं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा।

यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल मजबूत नेतृत्व में नहीं, बल्कि जवाबदेही, संवैधानिक मयार्दा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के सम्मान में निहित है। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश में तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी अपने ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। यह घटना भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दुखद और निर्णायक घटना बन गई।

आज के भारत के लिए इंदिरा गांधी की प्रासंगिकता

आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक, वैज्ञानिक, सामरिक और कूटनीतिक शक्ति को निरंतर विस्तार दे रहा है। ऐसे समय में इंदिरा गांधी के जीवन से कई महत्वपूर्ण संदेश ग्रहण किए जा सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय हितों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता किसी भी नेतृत्व की मूल पहचान होनी चाहिए। दूसरा, संकट के समय साहस और निर्णय क्षमता आवश्यक हैं। तीसरा, विज्ञान, कृषि, रक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता राष्ट्र की प्रगति के आधार स्तंभ हैं।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि सत्ता का सर्वोच्च दायित्व जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा किए बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति अधूरी है।

इंदिरा गांधी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास किसी व्यक्ति को केवल उसकी सफलताओं से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों के व्यापक प्रभावों से याद करता है। इसलिए उनके व्यक्तित्व का निष्पक्ष अध्ययन करना ही उनके प्रति वास्तविक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होगा।

स्मृतियों से आगे, विचारों तक

इंदिरा गांधी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सर्वोत्तम तरीका केवल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना नहीं, बल्कि राष्ट्रहित, महिला सशक्तीकरण, वैज्ञानिक सोच, आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने का संकल्प लेना है। वे भारतीय राजनीति की ऐसी प्रभावशाली शख्सियत थीं, जिनके निर्णयों ने देश की दिशा और दशा को प्रभावित किया। उनके जीवन में साहस और दृढ़ता के प्रेरक उदाहरण हैं, तो कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जो लोकतंत्र की मयार्दा और सत्ता की सीमाओं का बोध कराते हैं।

व्यक्तित्व की महानता का वास्तविक मूल्यांकन प्रशंसा और आलोचना, दोनों को स्वीकार करने में है। इंदिरा गांधी की जयंती हमें इसी संतुलित ऐतिहासिक दृष्टि के साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझने और लोकतांत्रिक भारत को अधिक सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है।



'आई प्ले रॉकी' के प्रीमियर पर कार्तिक आर्यन ने दिया सपनों, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास रखने के महत्व का संदेश

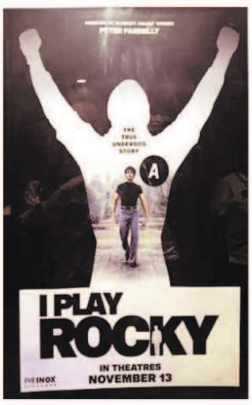
मुंबई फिल्म 'आई प्ले रॉकी' के प्रीमियर पर कार्तिक आर्यन ने सपनों, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास रखने के महत्व को लेकर एक दिल छू लेने वाला संदेश दिया। फिल्म को सपने देखने वालों और अपने सपनों पर विश्वास करने वालों की कहानी बताते हुए अभिनेता ने कहा कि यह उन सभी लोगों से जुड़ाव महसूस कराएगी, जिन्हें कभी न कभी यह कहा गया है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती।

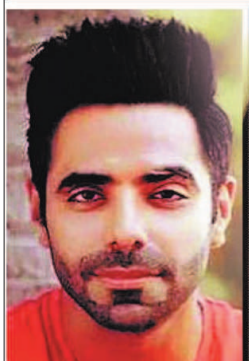
अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 'यह फिल्म उन सभी लोगों के बारे में है, जो सपने देखते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग, जिनसे अक्सर कहा जाता है कि 'नहीं हो सकता, यह तू कभी नहीं बन सकता, यह कभी नहीं बन सकती।' मेरा मानना है कि यह फिल्म आपको विश्वास दिलाएगी कि आप यह कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।'

अपने सफर से फिल्म की तुलना करते हुए कार्तिक ने बताया कि किस तरह ओरिजिनल फिल्म 'रॉकी' कई पीढ़ियों को प्रेरित करती आई है। उन्होंने यह भी साझा किया कि फिल्म का मशहूर गाना 'आई ऑफ द टाइगर' मुश्किल वक्त में उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, 'मेरे सफर में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं खुद को निराश महसूस करता हूं, तो 'आई ऑफ द टाइगर' एक ऐसा गाना है, जो मेरे लिए थीम सॉन्ग की तरह है और मुझे बहुत प्रेरित करता है। इसके बाद मैं बाकी चीजों से ध्यान हटाकर दोबारा अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू कर देता हूं।'

कार्तिक की ये बातें उस समय और भी खास हो गईं, जब उन्होंने ऐसे संदेश पर बात की, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके अपने सफर से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। चुनौतियों का सामना करने से लेकर अपनी अलग पहचान बनाने तक, कार्तिक की कहानी फिल्म के बड़े संदेश यानी दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। प्रीमियर पर उनकी स्पीच ने इस बात को रेखांकित किया कि आलोचनाओं, असफलताओं और दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखना कितना जरूरी है।

फिल्म को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए कार्तिक ने सिनेमा और 'आई प्ले रॉकी' के नाम एक जाम उठाया। साथ ही उन्होंने दर्शकों से फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन मिस न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वह खुद फिल्म देख चुके हैं और इसे दोबारा देखने की योजना बना रहे हैं। उनके मुताबिक, फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन दर्शकों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। प्रीमियर पर अपनी बातों के जरिए कार्तिक ने दर्शकों को एक खास संदेश दिया कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें और किसी को भी यह न कहने दें कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते।





'गन मास्टर जी9' में दिखेगा अपारशक्ति का खतरनाक अवतार

जब भी अपारशक्ति खुराना का नाम आता है, तो सबसे पहले स्त्री के प्यारे और मजेदार दोस्त बिट्टू की याद आती है, जो 'सॉफ्ट चिट्ठी, वॉर्म चिट्ठी' कहते नजर आते हैं। लेकिन अब अपारशक्ति ने अपने इस पुराने अंदाज को पीछे छोड़ दिया है। 'गन मास्टर जी9' में वह एक ऐसे खतरनाक विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं!

फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें अपारशक्ति का ऐसा रूप देखने को मिला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना तो तय है कि फिलहाल बिट्टू की मासूमियत को भूल जाइए, क्योंकि अब पर्दे पर उनका खतरनाक अंदाज छाने वाला है।

फिल्म में अपारशक्ति की पहली झलक से ही साफ हो जाता है कि वह इस बार एक अलग ही रूप में नजर आने वाले हैं। उनकी डरावनी नजरें, चेहरे के भाव और डायलॉग बोलने का अंदाज उनके किरदार को और भी खतरनाक बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्शन के मामले में भी वह किसी से पीछे नहीं हैं। उनके लड़ाई वाले दृश्य और जबरदस्त अंदाज उनके किरदार में एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। फिल्म में अपारशक्ति, इमरान हाशमी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं। ऐसे में दोनों के बीच होने वाली टक्कर को पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अपारशक्ति का लुक भी उनके इस नए किरदार को खास बनाता है। कंधों तक लंबे और बिखरे हुए बाल, रंग-बिरंगी प्रिंट वाली शर्ट, धातु के फ्रेम वाला चश्मा और बोलने का अलग अंदाज उनके किरदार को एकदम देसी और खुरदरा रूप देते हैं। खास बात यह है कि अपारशक्ति अपने किरदार को दमदार बनाने के लिए न तो किसी बड़े फिल्मी अंदाज में एंट्री लेते हैं और न ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। उनका अंदाज और उनका बेखौफ व्यक्तित्व ही उनकी मौजूदगी का एहसास करा देता है। ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड में अब विलेन के किरदारों को एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है और अपारशक्ति इस बदलाव की एक शानदार मिसाल बनने वाले हैं! 'गन मास्टर जी9 आगामी 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



साउथ एक्टर्स को हिंदी एक्सेंट के लिए ट्रोल करना 'बिल्कुल सही नहीं' है

'जेलर 2' की एक्ट्रेस अपेक्षा पोरवाल ने कहा कि साउथ इंडियन एक्टर्स को उनके हिंदी एक्सेंट के लिए ट्रोल किया जाना 'बिल्कुल सही नहीं' है। खास बातचीत में अपेक्षा ने बताया कि मजाक उड़ाने के बजाय एक्टर की मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए तो शायद वे खुद भी कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाएंगे।

अपेक्षा से पूछा गया, 'आजकल, साउथ इंडियन एक्टर्स को अक्सर सोशल मीडिया पर उनके हिंदी एक्सेंट और बोलने के तरीके के लिए ट्रोल किया जाता है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं? क्या उन आर्टिस्ट्स का मजाक उड़ाना सही है, जो दूसरी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं?'

यह समझाते हुए कि जिस भाषा को आप अच्छी तरह नहीं जानते, उसमें काम करना कितना मुश्किल है, उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई किसी खास भाषा में कम्फर्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सीखने और बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें उस कोशिश की तारीफ करनी चाहिए, न कि उस पर हंसना या उसे ट्रोल करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि अगर इन्हीं ट्रोल्स से दूसरी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो शायद वे खुद ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब कोई कड़ी मेहनत कर रहा हो और कोशिश कर रहा हो, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, बुराई नहीं।'

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल ही में अपने हिंदी एक्सेंट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में आने के दौरान 'एनिमल' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि अपने पूरे करियर में उन्हें अपने एक्सेंट को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि, रश्मिका ने कहा कि उन्होंने कभी भी आलोचना को अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री और भाषाओं में काम करने से रोकने नहीं दिया। रश्मिका ने बताया कि साउथ इंडिया से होने की वजह से उनका एक्सेंट नेचुरली आता है। एक्ट्रेस ने आगे जोर देकर कहा कि वह खुद को एक इंडस्ट्री तक लिमिट करने के बजाय कई भाषाओं में काम करना चाहती हैं।



नील आपको यह एहसास नहीं होने देते कि आप किसी सीनियर अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं



अभिनेत्री कशिका कपूर सॉन्ग 'बेवफा से' में नील नितिन मुकेश के साथ नजर आ रही हैं। उनके साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कशिका ने बताया कि वह कभी आपको यह एहसास नहीं होने देते कि आप किसी सीनियर अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं। अभिनेत्री कशिका कपूर ने बातचीत में अभिनेता नील नितिन मुकेश के साथ काम करने के अनुभव को मजेदार बताते हुए कहा, 'किसी सीनियर एक्टर से आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नील को इंडस्ट्री में कई साल काम करने का काफी अनुभव है। यह एक शानदार सीखने वाला अनुभव था और हमने खूब मस्ती भी की। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूं।' अभिनेत्री ने बताया कि शूट होने से पहले उन्हें गाने के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई गई थीं। उन्होंने कहा, 'नील नितिन मुकेश के आने से कुछ महीने पहले ही यह प्रोजेक्ट लॉक हो गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह गाना सच में बनेगा या इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आखिर में जब नील नितिन मुकेश फाइनल हुए तो मेकर्स ने गाने की धुन को देखते हुए इसमें एक डांस नंबर जोड़ने का फैसला किया। हमने रिहर्सल शुरू की और सब कुछ काफी अच्छा हुआ। तभी कहानी भी तैयार हुई।'

कशिका कपूर ने बताया, 'मुझे उम्मीद थी कि गाना लोगों को पसंद आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कमाल का है। मुझे लगता है जेन जी इस कहानी से इसलिए जुड़ रहे है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ऐसी चीजें काफी आम होती जा रही हैं। ओपन रिलेशनशिप और धोखा जैसी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं और शायद यही वजह है कि दर्शक इस गाने से इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'लोगों ने हमारे गाने को खुले दिल से अपनाया है और इतना प्यार दिया है। मैं इस रिस्पॉन्स के लिए बहुत आभारी हूं। लोग मेरे डांस और एक्सप्रेशन्स की तारीफ कर रहे हैं और मुझे लगता है सबको यह गाना पसंद आ रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है।



ग्लोबल म्यूजिक स्टेज पर दोसांझ, दुआ लीपा और मैडोना संग परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ

पंजाबी म्यूजिक का जलवा अब दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अपने म्यूजिक से इंटरनेशनल स्टेज पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में शामिल कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2027 में परफॉर्म करते नजर आएंगे। फेस्टिवल के आयोजकों ने अगले साल होने वाले इस इवेंट की कलाकारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिलजीत के साथ दुआ लीपा, टेम इम्पाला और एसजेडए जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा पॉप म्यूजिक की दिग्गज सिंगर मैडोना, जेआईएसओ, फोएबे ब्रिजर्स और रोबिन भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। कोचेला 2027 का आयोजन कैलिफोर्निया के इंडियो स्थित एम्पायर पोलो क्लब में होगा। यह फेस्टिवल दो वीकेंड में आयोजित किया जाएगा। पहला वीकेंड 9 से 11 अप्रैल और दूसरा वीकेंड 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। इस बार शुक्रवार को दुआ लीपा, शनिवार को टेम इम्पाला और रविवार को एसजेडए हेडलाइनर के तौर पर परफॉर्म करेंगे। तीनों कलाकार अपने अलग-अलग म्यूजिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जहां दुआ लीपा अपने पॉप म्यूजिक से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी, वहीं टेम इम्पाला साइकेडेलिक रॉक और एसजेडए आरएंडबी म्यूजिक का रंग जमाएंगी।

2023 में भी कोचेला का हिस्सा बने थे दिलजीत

भारतीय फैंस के लिए इस बार दिलजीत दोसांझ का नाम लिस्ट में शामिल होना खास है। दिलजीत इससे पहले साल 2023 में भी कोचेला फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं। उस समय उन्होंने पंजाबी भाषा में गाने गाकर दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान खींचा था। वह इस फेस्टिवल के मंच पर परफॉर्म करने वाले शुरुआती पंजाबी भाषा के कलाकारों में शामिल थे। अब 2027 में उनकी वापसी से एक बार फिर पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल पहचान मिलने की उम्मीद है।

मैडोना समेत ये बड़े कलाकार भी आएंगे नजर

इस बार कोचेला की लिस्ट में पॉप म्यूजिक की दिग्गज सिंगर मैडोना का नाम भी शामिल है। वह शुक्रवार को डांस टेंट में परफॉर्म करेंगी। वहीं डैडी यांकी को 'इन द डेजर्ट' स्पेशल बिलिंग दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की मशहूर जोड़ी जस्टिस भी अपने गाने 'ब्लाइंडेड बाय द लाइट्स' के साथ बंकर में डेब्यू करेगी। फेस्टिवल के पहले दिन यानी शुक्रवार को जारा लार्सन, स्टीव लैसी, जेआईएसओ, पैगी गू, केलेनी, लियोन थॉमस और जॉर्जियो मोरोडर जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। वहीं शनिवार को फोएबे ब्रिज, वीजर, रोबिन, मैनेस्किन, एनसीटी, लियोन ब्रिजेस, टिएस्टो, मार्टिन गैरिक और अंडरवर्ल्ड जैसे नाम शामिल हैं। रविवार को जॉन टॉलिवर, डोम डॉला, कायगो, एम्पायर ऑफ द सन, फोर टेट, द नेबरहुड, बेकी जी, बेबीमॉन्स्टर, विक्टोरिया मोनेट और जोरजा स्मिथ अपनी परफॉर्मेंस देंगे।

राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का महाकुंभ 23 से 27 नवंबर तक दुर्ग में

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

देश के 24 राज्यों के लगभग 500 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम, 'बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया' का मिलेगा प्रतिष्ठित खिताब





छत्तीसगढ़ की खेल नगरी दुर्ग एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं पावरलिफ्टिंग इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 23 से 27 नवंबर 2026 तक खालसा कॉलेज एवं खालसा स्कूल परिसर, आरटीओ कार्यालय के सामने, मालवीय नगर, दुर्ग में फेडरेशन कप एवं वेस्ट जोन राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से चयनित लगभग 500 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता, शक्ति एवं खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

दो चरणों में होंगी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं

प्रतियोगिता का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 23 नवंबर को फेडरेशन राष्ट्रीय इक्विप्ड (Equipped) तथा 24 नवंबर को क्लासिक (Classic) वर्ग की बालक एवं बालिका प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। द्वितीय चरण में 25 से 27 नवंबर तक वेस्ट जोन राष्ट्रीय सब-जूनियर (18 वर्ष तक), जूनियर (23 वर्ष तक) एवं सीनियर (ओपन) वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन मुकाबलों में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के नौ विभिन्न भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा होगी।

छत्तीसगढ़ की 62 सदस्यीय टीम करेगी प्रतिनिधित्व : इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 62 सदस्यीय महिला एवं पुरुष टीम भी अपनी चुनौती पेश करेगी। टीम में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी 22 नवंबर से दुर्ग पहुंचना प्रारंभ करेंगे।

बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब होगा मुख्य आकर्षण : इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण 'बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया' का प्रतिष्ठित खिताब रहेगा। विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं निर्धारित अंक प्रणाली के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। पावरलिफ्टिंग इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग महासंघ के निर्धारित नियमों के अनुरूप आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर के अनुभवी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों तथा जूरी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।

एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए होगा खिलाड़ियों का चयन : इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से अप्रैल 2027 में हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार दुर्ग में होने वाली यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण अवसर भी साबित होगी।

प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 23 नवंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे आयोजित होगा, जबकि समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 27 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे संपन्न होगा। इस भव्य राष्ट्रीय आयोजन से दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

खास खबर

मानव तस्करी और घरेलू हिंसा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला 23 को

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर



राष्ट्रीय महिला आयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 23 नवंबर 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में "मानव तस्करी एवं महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किए जाने हेतु सहमति प्राप्त हुई है। वहीं कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति हेतु भी सहमति प्रदान की गई है।

क्या होगा उद्देश्य?: इस कार्यशाला का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने तथा संबंधित कानूनों के प्रति जागरूकता एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और संबंधित संस्थाओं के प्रतिभागी शामिल होंगे। विशेषज्ञों द्वारा मानव तस्करी के कारण, पहचान, रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास तथा घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों, महिलाओं के अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

अध्यक्ष ने दी जानकारी : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने बताया कि यह कार्यशाला महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

कलेक्टर सिंह ने सभाकक्ष में ली राइस मिलर्स की बैठक, चावल जमा कराने और टैगिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के राइस मिलर्स और संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धान उठाव, कस्टम मिलिंग के तहत चावल (एफआरके व सामान्य) जमा कराने की प्रगति, गोदामों के भौतिक सत्यापन और टैगिंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने मिलर्स को निर्देश दिए कि दिसंबर माह के आवंटन और परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बकाया लॉट (विशेषकर एफआरके चावल) को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा (5 दिसंबर तक) में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने दैनिक आधार पर लॉट जमा करने का लक्ष्य तय करने और उसमें तेजी लाने को कहा।

अनुपस्थित मिलर्स और गोदामों के भौतिक सत्यापन के आदेश : बैठक में अनुपस्थित रहने वाले तथा पर्याप्त टैगिंग होने के बावजूद चावल जमा करने में देरी करने वाले मिलर्स (विशेषकर 500 क्विंटल से अधिक बकाया वाले) पर नाराजगी जताई गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित मिलों और किराए पर लिए गए गोदामों में रखे धान का अगले दो से तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराया जाए। इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नगर निगम रिसाली भिलाई और भिलाई-3 चरोदा में लेंगे सभा

कलेक्टर, एसएसपी ने किया चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग भिलाई नगर में आगामी दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिये।

कलेक्टर एवं एसएसपी ने नगर निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 दुर्गा चौक सभा स्थल, नगर निगम भिलाई के अंतर्गत आईआईटी मैदान तथा नगर निगम भिलाई-3 चरोदा अंतर्गत न्यायालयीन परिसर मैदान में मुख्यमंत्री का सभा की तैयारी का जायजा लिये। उन्होंने यहां मंच, ग्रीन हाउस, बैठक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, प्रवेश द्वार तथा विभागीय स्टॉल आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर एडीएम विरेन्द्र सिंह, नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त एस.के. सुन्दरानी, एसडीएम सोनाल डेविड, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता एवं प्रकाश चन्द्र सोनी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ए.के. भट्टाचार्य, जिला परिवहन अधिकारी मृत्युंजय पटेल, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ए.के. गौतम एवं संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय युवा उत्सव में 230 से अधिक कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा, 72 कलाकार राज्य स्तर के लिए चयनित

जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा 18 नवंबर को सतनामी आश्रम, सिविल लाइन कसारीडीह में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में दुर्ग, धमधा एवं पाटन विकासखंड के 230 से अधिक प्रतिभागियों ने 9 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती अल्का बाघमार मुख्य अतिथि एवं संयुक्त कलेक्टर उत्तम सिंह पंवारी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। समापन समारोह में पद्मश्री डॉ. आरएस बारते मुख्य अतिथि तथा पार्षद श्रीमती सरिता विनोद चंद्राकर शामिल हुईं। युवा उत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, नुक्कड़ नाटक, विकसित भारत चैलेंज ट्रैक एवं क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज सहित विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिले से चयनित 9 विधाओं के कुल 72 कलाकार राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेंगे। राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो कि 10 से 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा।

मारपीट से आहत व्यक्ति ने की आत्महत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-नेवई

मारपीट एवं बलवा कर व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में नेवई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त 2 लकड़ी के डंडे भी जप्त किए गए हैं।

मामला 4 नवंबर की रात्रि लगभग 10:40 बजे का है। मृतक श्रवण मंडावी, उम्र 54 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 34, दशहरा मैदान, नेवई के साथ उसके पड़ोसियों द्वारा नेवई बस्ती स्थित शिव मंदिर के पास पान ठेले के समीप विवाद करते हुए मारपीट की गई थी। आरोपियों द्वारा मृतक पर पान ठेले के पास ग्राहकों को शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए डंडे, चप्पल एवं हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई तथा बलवा किया गया। उक्त घटना से आहत एवं व्यथित होकर मृतक द्वारा स्वयं जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। उपचार हेतु शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटना की सूचना पर थाना नेवई में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाते हुए विसरा सुरक्षित रखा गया तथा मृतक के शरीर पर बाहरी चोटें होना उल्लेखित किया गया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल के पंचों, मृतक की पत्नी, परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन लिए गए। जांच में घटना दिनांक को आरोपियों द्वारा मृतक के साथ मारपीट एवं बलवा किए जाने तथा पूर्व में भी विवाद होने की जानकारी सामने आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 785/2026, धारा 108, 191(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता (इठर) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर 19 नवंबर 2026 को पांचों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त दो लकड़ी के डंडे जप्त किए गए। आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया, जहां से उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी में आलोक कुमार हुई, उम्र 52 वर्ष, निवासी खुशी किराना दुकान के पास, नेवई, सपना हुई, उम्र 42 वर्ष, निवासी नेवई बस्ती, पायल, उम्र 35 वर्ष, निवासी खुशी किराना स्टोर, नेवई बस्ती, शैलेन्द्री यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी लक्ष्मी पशु आहार के पास, नेवई और सरोज बाई यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी लक्ष्मी पशु आहार के पास, नेवई है।

कार्यवाही में थाना नेवई के निरीक्षक अनिल कुमार साहू, सउनि निगम पात्रे, प्रधान आरक्षक नंदलाल सिंह, प्रधान आरक्षक विजय सिंह, आरक्षक प्यारे लाल, आरक्षक विजय कुर्रे एवं आरक्षक देवप्रकाश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चेक बाउंस के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए आज विशेष लोक अदालत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के. विनोद कुजूर के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस) के अंतर्गत वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 नवंबर 2026 को किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक अनादरण से संबंधित लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण सुनिश्चित करना है, ताकि पक्षकारों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिल सके तथा उनके समय एवं धन की बचत के साथ विवादों का त्वरित समाधान हो सके।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने तथा इसकी जानकारी जिले के अधिकाधिक नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा व्यापक एवं बहुआयामी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, धमधा एवं भिलाई सहित विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

जनसामान्य तक विशेष लोक अदालत की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार वाहन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को विशेष लोक अदालत के आयोजन, उद्देश्य एवं लाभों की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा गांवों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर नागरिकों को धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया एवं विशेष लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही ऐसे लंबित प्रकरणों के पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें आपसी बातचीत, सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत के माध्यम से संबंधित पक्षकारों को अपने विवाद का आपसी सहमति से निराकरण कराने का अवसर प्राप्त होगा। लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारित आदेश को विधिक मान्यता प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कर सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बोझ को कम करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा जिले के समस्त संबंधित पक्षकारों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस विशेष लोक अदालत की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराने हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।

आरोप-प्रत्यारोप उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब

आदिवासियों के घर जलाने का आरोप, विधायक मंडावी ने वन विभाग को घेरा

नई दृष्टिबिंदु / बीजापुर

बीजापुर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आदिवासियों के साथ मारपीट करने और उनके घरों में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक के मुताबिक, ऊसूर ब्लॉक के ग्राम कोत्तापल्ली के पास रहने वाले आदिवासियों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की गई और 17 लोगों को जेल भेज दिया गया।

विधायक विक्रम मंडावी ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए भाजपा सरकार से सवाल किया कि गरीब आदिवासियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वन विभाग की इस कार्रवाई को सरकार का संरक्षण प्राप्त था? विधायक ने कहा कि जब सरकार नक्सलियों से बातचीत कर सकती है, तो आदिवासियों से संवाद कर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया?

विक्रम मंडावी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि



आदिवासियों के साथ कथित मारपीट और उनके घर जलाने के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया बयान

विधायक के आरोपों के बीच उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के मौजूदा हालात और नक्सलवाद से जुड़े लोगों की वापसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय तक नक्सलवाद से जुड़े रहे हैं, उनके संबंध में स्थानीय लोगों के मन में नाराजगी है। इस स्थिति को समझते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जा रहे हैं।

विजय शर्मा ने बताया कि अब तक तेलंगाना से 700 से अधिक लोग वापस लौट चुके हैं। उन्हें पुनर्वास केंद्र में छह महीने बिताने के बाद अपने घर जाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस अवधि में भी वे अपने गांव जा सकेंगे और परिजनों व स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी। सरकार की कोशिश है कि नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और क्षेत्र में शांति तथा विश्वास का माहौल बने। वहीं, बीजापुर में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों ने एक बार फिर आदिवासियों के अधिकारों और सरकारी कार्रवाई को लेकर बहस छेड़ दी है।

संभाग स्तरीय युवा संसद स्पर्धा में छात्राओं ने निभाई महत्वपूर्ण पक्ष-विपक्ष की भूमिका युवा संसद में कबीरधाम प्रथम, खैरागढ़ द्वितीय और बेमेतरा तृतीय स्थान पर

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई में आयोजित संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में कमिश्नर सत्यनारायण राठौर शामिल हुए। प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग के सात जिलों के स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक जिले से 55 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर श्री राठौर ने कहा कि युवा संसद प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक और देश से जुड़े विषयों की जानकारी भी रखनी चाहिए। ऐसे आयोजन बच्चों को जागरूक बनाते हैं और भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कबीरधाम, द्वितीय स्थान खैरागढ़ तथा तृतीय स्थान बेमेतरा जिले के प्रतिभागियों ने प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्राफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त विजेता प्रतिभागियों को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कबीरधाम के लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रधान मंत्री तथा खैरागढ़ के नेता प्रतिपक्ष एवं गृह मंत्री, बेमेतरा के वित्त मंत्री एवं राजनांदगांव के मार्शल के लिए प्रोत्साहन राशि रुपए 21-21 सौ रुपए प्रदान किये गए।

प्रभारी सचिव ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर परखी व्यवस्था, किसानों की सुविधाओं का लिया जायजा

पनेका, कोसमंदा, धरमपुरा, बिरकोना सहित 8 केंद्रों में खरीदी, तौल, गुणवत्ता का किया निरीक्षण, रकबा व पंजीयन संबंधी त्रुटियों का सर्वोच्च प्राथमिकता से सुधार करने के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है। खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने जिले के प्रभारी सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के साथ जिले के 8 धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पनेका, कोसमंदा, धरमपुरा, बिरकोना, सोनपुरी रानी, धमकी, बम्हनी एवं रेंगाखार खुर्द केन्द्रों में खरीदी, तौल, गुणवत्ता जांच, बारदाना एवं भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी किसानों का धान सुचारू रूप से खरीदा जाए और खरीदी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने किसानों से सीधे बातचीत कर टोकन वितरण, धान विक्रय एवं भुगतान की जानकारी ली। छोटे किसानों को टोकन देने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आद्रतामापी मशीन से धान की नमी जांची तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से वजन की सटीकता का परीक्षण किया। धान की गुणवत्ता जांच के लिए ढेरी बनाकर परीक्षण करने और निर्धारित नमी के अनुरूप धान लाने के लिए किसानों को जागरूक करने कहा। धान की स्टेकिंग व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि खरीदी के दिन ही धान का व्यवस्थित स्टेकिंग कराया जाए, जिससे धान सुरक्षित रहे और गुणवत्ता प्रभावित न हो।



प्रभारी सचिव डॉ भारतीदासन ने बारदाना की गुणवत्ता जांच तथा पर्याप्त तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, ड्रेनेज एवं सीसीटीवी सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने धान के भंडारण के लिए पहले से ही विकल्पित जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंप्यूटर में टोकन सॉफ्टवेयर, किसानों के पंजीयन, रकबा, अनुमानित खरीदी एवं भुगतान की जानकारी ली। खरीदी संबंधी रजिस्टरों का नियमित संधारण करने तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं समिति प्रबंधकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देने कहा, ताकि तकनीकी त्रुटियां कम हों और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। निरक्षण के दौरान खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन, डीएम ओ किशोर चंद्रा, सीसीबी नोडल आर पी मिश्रा, सहकारिता उपायुक्त आकाश पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने किसानों के रकबा संबंधी त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि पिछले वर्ष एग्रीस्टेक में पंजीकृत किसानों का रकबा शून्य अथवा पूर्व की तुलना में कम प्रदर्शित होने संबंधी त्रुटियों का सुधार समिति स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। पंजीयन संबंधी त्रुटियों के कारण अन्य फसल प्रदर्शित होने तथा किसानों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए समिति स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं समिति प्रभारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी के दौरान किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, ताकि किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

खास खबर

अवैध धान भंडारण पर दो व्यापारियों से 40 क्विंटल धान जब्त, कोचिया, बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई



नई दृष्टिबिंदु / मोहला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार मोह ला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान भंडारण एवं कोचिया, बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से भंडारित कुल 40 क्विंटल धान जब्त किया है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहला में जांच के दौरान व्यापारी श्रवण साहू के प्रतिष्ठान एस.के. ट्रेडर्स से 15 क्विंटल तथा सलीम खान के प्रतिष्ठान एच.वी. एंड संस से 25 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 40 क्विंटल धान जब्त किया। संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धान भंडारण, परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में निजी सीबीएसई विद्यालय और मल्टीप्लेक्स सहित मिनी–मॉल की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित

खैरागढ़। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में निजी सीबीएसई विद्यालय और मल्टीप्लेक्स सहित मिनी–मॉल की स्थापना के लिए निजी निवेशकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। इसका उद्देश्य जिले में शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार की सुविधाओं का विस्तार करना तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

दोनों परियोजनाओं के लिए अलग–अलग न्यूनतम निवेश 5 करोड़ रुपये, 6 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन इच्छुक निवेशक 6 दिसंबर 2026 तक विभागीय पोर्टल https://invest.cg.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी विद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का निवेश, कक्षा पहली से बारहवीं तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता और कम से कम 500 विद्यार्थियों की क्षमता अनिवार्य है। विद्यालय में पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, छात्रावास और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

मल्टीप्लेक्स सहित मिनी–मॉल की स्थापना के लिए भी न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है। मिनी–मॉल का कारपेट एरिया 8,000 वर्गफीट से अधिक होना चाहिए। मल्टीप्लेक्स में कम से कम दो स्क्रीन होनी चाहिए और प्रत्येक स्क्रीन के लिए न्यूनतम 100 सीटों की व्यवस्था अनिवार्य है। मिनी–मॉल में कम से कम पांच रिटेल स्टोर भी होने चाहिए। आवेदन संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए निवेशक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, भूतल, गीता कॉम्प्लेक्स, साई मंदिर के पास, कवर्धा रोड, खैरागढ़ में संपर्क कर सकते हैं।

अनुपयोगी शासकीय वाहन की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित

राजनांदगांव। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के अनुपयोगी शासकीय वाहन सुमो गोल्ड सीएक्स सीजी 02–7494 का विक्रय (नीलामी) बंद निविदा के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक क्रेता 26 नवम्बर 2026 को शाम 5.30 बज तक पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित कर सकते है। प्राप्त निविदा फार्म को 27 नवम्बर 2026 को दोपहर 3 बजे जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के कक्ष में खोली जाएगी। निविदा फार्म 23 नवम्बर 2026 तक दोपहर 12 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 116 से प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण



नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने आज नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ, चिचोली, मारो एवं झिलगा स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर धान खरीदी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान मंत्री बघेल ने केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं खरीदी प्रक्रिया की जानकारी ली तथा किसान भाइयों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। मंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी सोच एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 3,100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 13,839 रूपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ष विशेष व्यवस्था के तहत 21 क्विंटल से कम धान विक्रय करने वाले पात्र किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा।

किसान घर बैठे कटवा रहे टोकन, केंद्रों में बारदाना और तौल की सुगम व्यवस्था

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में कृषक उन्नति योजना के तहत पूरे प्रदेश सहित महासमुन्द जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तिहार सुचारू रूप से जारी है। जिले के उपार्जन केंद्रों में किसान पूरे उत्साह के साथ अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के हाटोकन तुंहर हाथहा एप ने किसानों की राह और आसान कर दी है, जिससे उन्हें घर बैठे टोकन मिल रहा है और खरीदी केंद्रों में अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिली है। बागबाहरा ब्लॉक के ग्रामीण सहकारी समिति सुखरीडबरी में कुल 1127 किसान पंजीकृत है। समिति ने इस सीजन में 76896 क्विंटल अनुमानित खरीदी होने की बात कही। 19 नवंबर को 18 किसान धान विक्रय करने पहुंचे जिनसे 636 क्विंटल धान खरीदा गया। इसी तरह 20 किसानों से 756 क्विंटल धान खरीदी की गई। धान बेचने पहुंचे किसानों ने केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना की। ग्राम कस्तूरबोड से 40 कट्टा धान लेकर पहुंचे किसान शिवलाल पटेल और ग्राम दावनबोड से 229 बोरा धान बेचने आए सुरेश कुमार धुर्वे ने बताया कि समिति में बिना किसी परेशानी के बारदाना मिल रहा है और धान का तौल भी समय पर व व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। डिजिटल सुविधा का लाभ उठा रहे ग्राम अनवरपुर के किसान संतोष पटेल ने बताया कि उन्होंने बीते 16 नवंबर को अपना धान बेचा। उन्हें टोकन के लिए समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि घर बैठे ही टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से टोकन कटवाया और केंद्र में पहुंचकर आसानी से 32 क्विंटल 50 किलो धान की बिक्री की। किसानों ने राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 13,839 रुपये की राशि दिए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि सरकार के किसान हितैषी निर्णयों से उन्हें सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री बघेल ने संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का सम्मान, उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे।

साल्हेवारा बांध में NDRF का आपदा बचाव प्रदर्शन, बाढ़ और डूबने से बचने की सिखाई तकनीकें



नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़–छुईखदान–गंडई

खैरागढ़ तहसील अंतर्गत साल्हेवारा बांध में NDRF की 03 BN कटक (ओडिशा) की 30 सदस्यीय टीम द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमांडेंट आदित्य रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में NDRF के जवानों एवं गोताखोरों ने बाढ़ तथा जल दुर्घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।

क्या–क्या सिखाया गया? : कार्यक्रम के दौरान बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने, नाव पलटने की स्थिति में मछुआरों एवं पर्यटकों को बचाने तथा पानी में डूबे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।

इसके साथ ही डूबने की घटना के बाद पीड़ित को दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा, CPR एवं एयर फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया। NDRF की टीम ने घरेलू उपयोग की खाली पानी की बोतलों, तेल के पीपों एवं जरीकेन आदि से इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग डिवाइस तैयार कर बाढ़ के दौरान उनके उपयोग से बचाव के तरीके भी समझाए।

कलेक्टर-SP रहे मौजूद : इस अवसर पर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंदवाल एवं पुलिस अधीक्षक लक्ष्य विनोद शर्मा अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, SDRF एवं फायर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

उद्देश्य - ग्रामीण पहले खुद को बचा सकें : कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली व्यावहारिक बचाव तकनीकों से अवगत कराने के साथ–साथ स्थानीय ग्रामीणों को भी आपदा प्रबंधन एवं आत्मरक्षा के इन तरीकों के प्रति जागरूक करना रहा, ताकि किसी आपातकालीन परिस्थिति में प्रशासन एवं बचाव दल के पहुंचने से पूर्व ग्रामीणजन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वयं की सुरक्षा एवं प्राथमिक बचाव कार्य कर सकें।

इस प्रकार कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

धान बेचने पहुंचे किसान भूपेंद्र को दोहरी राहत, उपज का उचित मूल्य और अतिरिक्त सहायता

प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता से खेती को मिलेगा संबल

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के साथ कृषक उन्नति योजना के माध्यम से अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है। इसका लाभ ग्राम खण्डसरा के किसान भूपेंद्र चंद्राकर के परिवार को भी मिल रहा है। वे अपने पिता केशरी प्रसाद चंद्राकर की ओर से उत्पादित 99.60 क्विंटल धान बेचने उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टोकन और उपार्जन केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाओं से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले से आसान और सुविधाजनक हुई है।

प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता से किसानों को राहत

भूपेंद्र चंद्राकर ने कृषक उन्नति योजना को किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि खरीफ वर्ष 2026–27 के लिए पात्र धान उत्पादक किसानों को सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है। योजना की विशेषता यह है कि किसान यदि निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम उपार्जन सीमा से कम धान भी बेचता है, तब भी पात्र सत्यापित रकबे के अनुसार उसे निर्धारित आदान सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई बार मौसम और खेती की परिस्थितियों के कारण किसान अपेक्षित उत्पादन नहीं ले पाते। ऐसे में सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस राशि से खेती की लागत और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।



किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

भूपेंद्र चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी की सुविधाजनक व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए लाभकारी है। ऑनलाइन टोकन जैसी सुविधाओं से धान विक्रय आसान हुआ है और आदान सहायता से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने किसानों के हित और सम्मान को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कृषक उन्नति योजना और सुव्यवस्थित धान खरीदी व्यवस्था से किसानों को उपज का उचित मूल्य, विक्रय में सुविधा तथा खेती के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल रही है। शासन की इन पहलों से किसान परिवारों की आर्थिक मजबूती और खेती–किसानी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है।

कार्रवाई

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी, चार दिनों में 4160 किसानों से 15 हजार 442 मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन

चौथे दिन 1274 किसानों से 4 हजार 832 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में किसान उत्साहपूर्वक अपनी उपज का विक्रय करने पहुंच रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। धान खरीदी के चौथे दिन 18 नवम्बर 2026 को जिले के 1274 किसानों से कुल 4 हजार 832.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस प्रकार जिले में धान खरीदी प्रारंभ होने से अब तक चार दिनों में कुल 4160 किसानों से 15 हजार 442.88 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 नवम्बर 2026 को जिले के 122 धान उपार्जन केन्द्रों के लिए कुल 1343 टोकन जारी किए गए थे। इन टोकनों के माध्यम से 5 हजार 538.10 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत था। जारी टोकनों में से 94.86 प्रतिशत किसानों ने उपार्जन केन्द्रों में पहुंचकर अपना धान विक्रय किया। वहीं 19 नवम्बर 2026 को धान विक्रय के लिए जिले के 121 उपार्जन केन्द्रों में कुल 1425 टोकन जारी किए गए हैं। इन टोकनों के माध्यम से 5 हजार 848.32 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत है।



अवैध धान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, एक दिन में 876 कट्टा धान जप्त

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं उपार्जन केन्द्रों में अवैध धान खपाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 नवम्बर 2026 को जिले में अवैध धान के 5 प्रकरण दर्ज कर कुल 876 कट्टा अर्थात 350 क्विंटल धान जप्त किया गया। मंडी डोंगरगढ़ द्वारा ग्राम द्वारा एवं देवकट्टा में 2 प्रकरणों में कुल 90 कट्टा अर्थात 36 क्विंटल धान जप्त किया गया। इसी प्रकार मंडी राजनांदगांव द्वारा ग्राम गठुला एवं भेड़ीकला में 2 पोहा उद्योगों से कुल 386 कट्टा अर्थात 154 क्विंटल धान जप्त किया गया। जांच के दौरान लाइसेंस की तय सीमा से अधिक धान का संग्रहण किए जाने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण जप्ती की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त धान उपार्जन केन्द्र खैरझिटी में एक व्यक्ति द्वारा रबी फसल का धान खपाने का प्रयास किए जाने पर नायब तहसीलदार राजनांदगांव द्वारा कार्रवाई करते हुए 400 कट्टा अर्थात 160 क्विंटल धान जप्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिले में 17 नवम्बर 2026 तक अवैध धान के 13 प्रकरणों में 3039 कट्टा अर्थात 1378 क्विंटल धान जप्त किया गया था। वहीं 18 नवम्बर को 5 नए प्रकरणों में 876 कट्टा अर्थात 350 क्विंटल धान जप्त किया गया। इस प्रकार जिले में अब तक अवैध धान के कुल 18 प्रकरणों में 3915 कट्टा अर्थात 1728 क्विंटल धान जप्त किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान 2 वाहनों की भी जप्ती की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है।

नीट 2027 भी पेन-पेपर से ही होने के आसार

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर अमल मुश्किल

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 2027 में होने वाली नीट-यूजी परीक्षा पेन-पेपर मोड (ओएमआर शीट) से ही होने के आसार हैं। नीट पेपर लीक पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इस साल मई में घोषणा की थी कि 2027 से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) रहेगी। फिलहाल इस पर अमल मुश्किल दिख रहा है।

परीक्षा एनटीए को करवानी है। लेकिन, यह पेन-पेपर मोड में हो या सीबीटी में, इसका फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही परीक्षा के मोड पर फैसला हो सकेगा।

जनवरी में आएगी नीलेकणि कमेटी की रिपोर्ट

परीक्षा सुधार से जुड़ी इस कमेटी की रिपोर्ट पहले अक्टूबर में आनी थी। लेकिन, अब जनवरी 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद 25 लाख अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र और परीक्षा की शिफ्ट संभालने जैसे कामों के लिए समय बहुत कम बचेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की चुनौती समझने के लिए एनटीए की जेईई मेन से तुलना कर सकते हैं। जेईई के अप्रैल 2026 सत्र में 9 शिफ्ट में 584 केंद्रों पर परीक्षा हुई। नीट में 22.7 लाख छात्रों के लिए क्षमता तैयार करनी होगी।



विशेषज्ञ की राय: 20 शिफ्टों का हाइब्रिड मोड अपनाएं

महेश्वर पेरी, फाउंडर, कैरियर 360 के अनुसार, जेईई मेन के अप्रैल सत्र के औसत के आधार पर एक शिफ्ट में 1.23 लाख छात्र परीक्षा दे सकते हैं। यही क्षमता नीट पर लागू करें तो 20 शिफ्ट होंगी। रोज दो शिफ्ट हों तो परीक्षा 10 दिन में होगी। पूरी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने के लिए करीब 10,750 केंद्र चाहिए होंगे।

सीबीटी मोड में 20 शिफ्टों में परीक्षा होती है तो हरेक का अलग प्रश्नपत्र तैयार करना होगा। कठिनाई के स्तर में अंतर संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी होगा। जेईई मेन में यह व्यवस्था है। नीट में लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। नीट के आधे सवाल बायोलॉजी से होते हैं। अलग-अलग शिफ्टों में प्रश्नों के कठिनाई स्तर का आकलन और संतुलन करना आसान नहीं होगा। इसके साथ कंप्यूटर, बिजली, इंटरनेट, तकनीकी कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी।

इतनी बड़ी परीक्षा एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं दिखता। सीबीटी के लिए 20 शिफ्टों के लायक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। इसके लिए बहुत कम समय बचा है। यदि नीलेकणि कमेटी सीबीटी मोड की सिफारिश करती है, तब भी पेन-पेपर से सीधे सीबीटी पर जाने के बजाय हाइब्रिड मोड बेहतर विकल्प हो सकता है। बड़े और मेट्रो शहरों में सीबीटी का विकल्प दे सकते हैं, जबकि छोटे शहरों में एक-दो साल तक पेन-पेपर मोड जारी रख सकते हैं। इस दौरान सीबीटी केंद्रों का नेटवर्क धीरे-धीरे बढ़े और पूरी परीक्षा सीबीटी मोड में बदली जाए। जेईई को पेन-पेपर से सीबीटी मोड में लाते समय भी हाइब्रिड मोड अपनाया गया था।

अभी 18 राज्यों से ही राय ले पाई है कमेटी

नीट में बदलाव को लेकर कमेटी राज्यों से सुझाव ले रही है। 18 राज्यों के सुझाव आए हैं। कई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों को मेडिकल एडमिशन में वेटेज देने की मांग की है। तमिलनाडु पेन-पेपर मोड के पक्ष में है। तीन दक्षिणी राज्य सीबीटी के पक्ष में हैं। साल में एक से अधिक बार नीट कराने और सीबीटी के शुरूआती चरण में ऑनलाइन तथा ओएमआर दोनों विकल्प जैसे सुझाव हैं।

जमीन बिक्री के नाम पर 20 लाख 95 हजार की ठगी, जमीन दूसरे को बेच दी, दो गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रानीतराई-दुर्ग

थाना रानीतराई पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर 20 लाख 95 हजार रुपये लेकर संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

क्या था मामला? : 1 नवंबर 2026 को ग्राम बीजाभाठा निवासी प्रार्थी ने थाना रानीतराई में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में आरोपी तुकेश साहू ने अपनी जमीन बिक्री करने के नाम पर प्रार्थी से कुल 20,95,000 रुपये प्राप्त किए थे। प्रार्थी द्वारा जमीन के संबंध में जानकारी लेने एवं अपनी दी गई रकम वापस मांगने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। इसी दौरान आरोपी ने उक्त जमीन को गुपचुप तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच दिया।

इस कार्य में आरोपी उमेंद्र कुमार साहू निवासी जुनवानी ने भी सहयोग करते हुए जमीन बिक्री की प्रक्रिया निष्पादित कराने में भूमिका निभाई। प्रार्थी की शिकायत पर थाना रानीतराई में अपराध क्रमांक 109/2026, धारा 420, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस टीम ने विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से प्रकरण से संबंधित बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की मूल प्रतियां जप्त की गई। दोनों आरोपियों को 20 नवंबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी में तुकेश साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बीजाभाठा, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग और उमेंद्र कुमार साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम जुनवानी, थाना भखारा, जिला धमतरी शामिल है।

क्या-क्या जप्त हुआ? : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग, शाखा जामगांव आर की 01 बैंक पासबुक, एचडीएफसी बैंक की 01 बैंक पासबुक, आधार कार्ड की मूल प्रति, पैन कार्ड की मूल प्रति।

पुलिस टीम : इस कार्यवाही में थाना रानीतराई के निरीक्षक हुबलाल चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक संतोष साहू, आरक्षक एस. दिनेश, चन्द्रहास वर्मा, फिरोज खान एवं फाल्गो वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि जमीन अथवा अन्य अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय करते समय संबंधित भूमि के स्वामित्व, दस्तावेजों एवं पूर्व में हुए सौदों की विधिवत जांच अवश्य करें। जमीन के लेन-देन में बिना उचित दस्तावेज एवं कानूनी प्रक्रिया के बड़ी धनराशि का भुगतान न करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को सूचना दें।

महिला स्व-सहायता समूह की 4,14,800 रुपये की राशि का गबन, समूह अध्यक्ष हुई गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / पुलगांव-दुर्ग

ग्राम नागपुरा के सपूरा माता सहायता समूह की 12 महिला सदस्यों की शिकायत पर थाना पुलगांव पुलिस ने समूह की अध्यक्ष को 4,14,800 रुपये की राशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

क्या था मामला? : ग्राम नागपुरा की महिलाओं ने 09 जून 2022 को सपूरा माता सहायता समूह का गठन किया था, जिसमें कुल 12 महिलाएं सदस्य थीं। समूह के संचालन एवं आर्थिक लेन-देन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा नागपुरा में बैंक खाता खोला गया था। समूह की सदस्य महिलाएं नियमित रूप से बचत राशि जमा करती थीं तथा समूह के खाते में शासकीय सहायता राशि भी प्राप्त हुई थी।

समूह की अध्यक्ष कीर्ति मंडले द्वारा सदस्यों से समय-समय पर राशि प्राप्त की जाती थी। 18 नवंबर 2026 को समूह की महिलाओं ने बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी ली, तो अपेक्षित राशि खाते में उपलब्ध नहीं मिली। इस संबंध में अध्यक्ष से पूछताछ करने पर उसके द्वारा राशि खर्च हो जाना बताया गया तथा बैंक पासबुक एवं हिसाब-किताब उपलब्ध कराने में टालमटोल की गई। इसके पश्चात समूह की महिलाओं ने आपसी जानकारी एकत्रित कर कुल 4,14,800 रुपये की राशि के गबन के संबंध में थाना पुलगांव में लिखित शिकायत प्रस्तुत की।



पुलिस की कार्रवाई : शिकायत पर थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 1017/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कीर्ति मंडले को 20 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी में कीर्ति मंडले, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नागपुरा, चौकी नगपुरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग है।

पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से अपील की है कि समूह की बचत राशि एवं शासकीय सहायता राशि का लेन-देन पारदर्शी तरीके से करें। बैंक खाते का नियमित मिलान करें तथा पासबुक, बैंक विवरण एवं आय-व्यय का रिकॉर्ड सभी सदस्यों के साथ साझा करें। किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता अथवा धोखाधड़ी की आशंका होने पर तत्काल संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

1400 साल पुरानी मूर्ति अमेरिका से भारत आई, पर छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रही!

एएसआई मांग रहा 59 साल पुरानी एफआईआर, रिकॉर्ड गायब

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर से 15 अप्रैल 1967 में चोरी हुई अवलोकितेश्वर की कांस्य मूर्ति अमेरिका-मैनहट्टन के एक म्यूजियम से बरामद हुई है। अमेरिका ने 1400 साल पुरानी (7वीं सदी की) इस मूर्ति की कीमत 20 करोड़ रुपये आंकी है। इसे भारत सरकार को लौटा भी दिया गया है, मगर इसकी छत्तीसगढ़ वापसी में एक बड़ा पेंच फंस गया है।

सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु की जांच में सामने आया है कि अरकको मूर्ति चोरी की 59 साल पुरानी FIR चाहिए, जो संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पास नहीं है। रिकॉर्ड मिसिंग है या दीमक खा चुकी है। बस इन मूर्तियों की चोरी की तारीख, डिटेल जैसे नाम, कब-कहां से मिली, संग्रहालय के एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज है। मगर फोटो चस्पा नहीं है। यही वजह है कि अरकको जवाब नहीं भेजा जा सका।

उधर, इन्वेस्टिगेशन में इस मूर्ति के सिरपुर, रायपुर के होने के प्रमाण मिले हैं। मैनहट्टन अटॉर्नी ऑफिस और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय वस्तु-मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर नेटवर्क से जुड़े लोगों से पूछताछ में मूर्ति के रायपुर संग्रहालय से होना पाया गया। सुभाष को 2011 में इंटरपोल ने जर्मनी में गिरफ्तार किया। प्रत्यर्पण कर 2012 में भारत लाया गया, तब से वह तमिलनाडु त्रिची सेंट्रल जेल में बंद है।

7 महीने से चल रहा है पत्राचार, फिर भी नहीं मिली मूर्ति

राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्री और अरकके बीच 7 महीने से पत्राचार जारी है -

18 मई 2026 - संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल का केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र। जवाब - मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। अरक से संपर्क करें।

10 जुलाई 2026 - संस्कृति संचालक डॉ. संजय कनौजे का महानिदेशक ASI को पत्र। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा राज्य की अमूल्य पुरातात्विक धरोहर है। इसकी वापसी के संबंध में अवगत करवाएं। जवाब - इससे संबंधित दस्तावेज सबमिट करें।

27 अगस्त 2026 - ASI का जवाब। मूर्ति चोरी की FIR दें। (जवाब अब तक नहीं भेजा गया।)

मैनहट्टन की रिपोर्ट में क्या लिखा है?

मैनहट्टन के अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में लिखा है - जब्त मूर्ति रायपुर संग्रहालय की है। यह दोहरे कमल पर विराजमान अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा है। आधार सिंहों से सुसज्जित सिंहासन पर बना है। इस पर शिल्पकार का नाम द्रोणादित्य और स्थान सिपुर (अभी सिरपुर) दर्ज है, जो छत्तीसगढ़ में है।

यह मूर्ति वर्ष 1939 में लक्ष्मण मंदिर के पास मिले कांस्य प्रतिमाओं के बड़े संग्रह का हिस्सा थी। इसे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में रखा गया। 1982 तक यह प्रतिमा संग्रहालय से चोरी कर अमेरिका पहुंचा दी गई थी। 2014 तक न्यूयॉर्क के निजी संग्रहकर्ता के पास पहुंची।

वर्ष 2025 में इसे कपूर के न्यूयॉर्क वेयर हाउस से जब्त किया गया। अटॉर्नी एल्विन एल. ब्रैग जूनियर के अनुसार भारत को 657 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई गईं, इनकी कीमत 116 करोड़ रुपये हो सकती है। ये कलाकृतियां अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं।

अवलोकितेश्वर शब्द का अर्थ : संसार के प्राणियों की ओर करुणा पूर्वक दृष्टि रखने वाले। ऐसा महापुरुष जिसने बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता हासिल कर ली हो, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया हो।

सिरपुर में मिला था मूर्तियों का भंडार : महासमुंद के सिरपुर में 1939 से 1952 के बीच खोदाई में बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजुश्री और तारा सहित 67 प्रतिमाओं का भंडार मिला था। इन्हें रायपुर संग्रहालय में रखा गया। इनमें से बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि और तारा की मूर्तियां चोरी हुई थीं। इन मूर्तियों का निर्माण उत्तर-गुप्त काल में पांडुवंशी राजवंश के शासनकाल में हुआ था।

विशेषज्ञ की राय : डॉ. किरीट एल. मंडोकी, पुरातत्ववेत्ता, मुंबई (कई मूर्तियों की पहचान में अरकको मदद की) ने कहा - सुभाष कपूर और पूर्व में उनके पिता यानी 2 जनरेशन से मूर्तियों का कारोबार करते आ रहे हैं। सुभाष ने इसे इंटरनेशनली ऑपरेट किया, एक रैकेट और स्मगलिंग नेटवर्क की तरह। सच है कि सबसे ज्यादा मूर्तियां तमिलनाडु से चोरी हुईं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो तो यह रैकेट तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। देशभर में फैला है क्योंकि मूर्तियां तो देशभर से चोरी हुई हैं।

तीसरी बार भेजेंगे दस्तावेज : डॉ. संजय कनौजे, संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय छत्तीसगढ़ ने कहा - मैनहट्टन अटॉर्नी जनरल से जुड़े जो दस्तावेज दिए हैं, उन्हें अटैच करके तीसरी बार अरकको पत्र लिखने जा रहे हैं। उन्होंने अरकमांगी है, उसकी खोजबीन करवाई जा रही है। लेकिन मैनहट्टन के दस्तावेज मूर्ति छत्तीसगढ़ की है, इस क्लेम के लिए पर्याप्त हैं।

EPFO का बड़ा फैसला : अब PF से 90% तक निकाल सकेंगे पैसा

रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी किस्त

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बोर्ड ने अपनी बैठक में कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने खाते से 90% तक रकम निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75% थी।

क्या बदला? जानिए 5 बड़े फैसले

न्यूनतम बैलेंस घटा - 25% से 10%: बोर्ड ने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को 25% से घटाकर 10% कर दिया है। इसका मतलब अब आप अपनी जमा राशि का 90% तक इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अपनी बचत इस्तेमाल करने की ज्यादा आजादी मिलेगी।

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) : रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' लाया गया है। इसके तहत पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय, हर महीने किस्तों में भी ले सकेंगे। बचे हुए पैसे पर ब्याज भी मिलता रहेगा। सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार या नॉमिनी को यह पैसा मिलेगा।



नौकरी छूटने पर अब 2 महीने में फाइनल सेटलमेंट : नौकरी छूटने पर पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए अब 12 माह का इंतजार नहीं करना होगा। बोर्ड ने 2 महीने के बाद फाइनल सेटलमेंट का पुराना नियम फिर से लागू कर दिया है। हालांकि पेंशन निकालने के लिए 36 महीने ही इंतजार करना होगा।

वेतन सीमा 15 हजार से बढ़कर 25 हजार: अनिवार्य पीएफ की वेतन सीमा भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। इससे करीब 1 करोड़ नए कर्मियों को लाभ होगा।

सावधान भी रहें : विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार पैसा निकालने से कंपाउंडिंग का फायदा कम हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट के समय आपका फंड कम पड़ सकता है। 90% पैसा निकालने और इंतजार की अवधि 12 से 2 महीने होने से नौकरी गंवाने वाले और नई नौकरी के बीच के दौर में फंसे या अचानक किसी आर्थिक जरूरत का सामना कर रहे कर्मचारियों को फायदा होगा।

नोट: नए नियमों के लागू होने की अधिसूचना का इंतजार करें। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट / अपने UAN पोर्टल पर ही आवेदन करें, किसी बिचौलिए के झांसे में न आएं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

सोनम चंदवानी, मैनेजिंग पार्टनर, केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के अनुसार, 50 लाख के ईपीएफ फंड पर हर माह 30 हजार रुपये निकालते रहें तो भी 20 साल बाद 75 लाख रुपये बचेंगे।

मान लें, रिटायरमेंट पर आपके ईपीएफ फंड में कुल 50 लाख रुपये हैं। 8.25% वार्षिक ब्याज दर पर हर महीने लगभग 0.6875% ब्याज बनेगा। यदि 20 साल तक हर महीने 30 हजार निकालते रहें तो कितना बचेगा।

इसका गणित समझिए

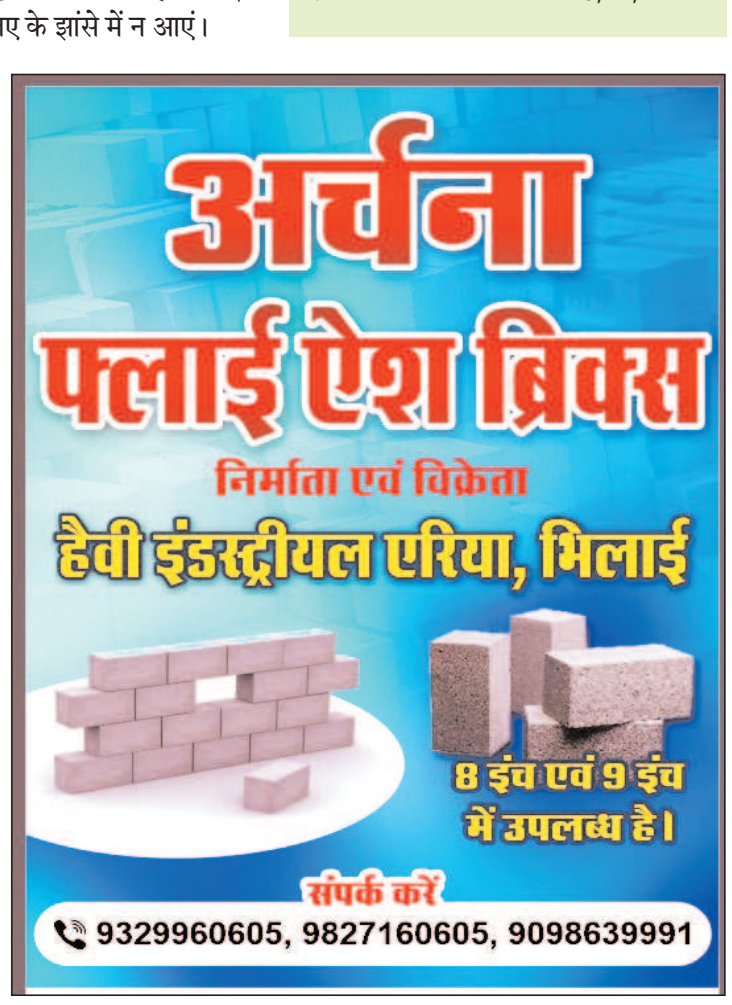
समयावधि	कुल निकासी	कुल बैलेंस
1 साल	3.6 लाख	50,08,366
5 साल	18 लाख	50,51,961
10 साल	36 लाख	53,08,311
15 साल	54 लाख	57,73,385
20 साल	72 लाख	75,33,184



20 लीटर महुआ शराब जप्त, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देश व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में आज आरोपी लखन लाल आ. माघव, सा. शीतलापारा घोरारी थाना रानीतराई पाटन जिला-दुर्ग के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं आरोपी भागचन्द्र आ. जवाहर लाल सा. शीतलापारा घोरारी, थाना रानीतराई पाटन जिला-दुर्ग के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 20 लीटर शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) का उल्लघंन किये जाने पर 02 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। उक्त प्रकरणों की विवेचना आबकारी उप निरीक्षक रामानंद दीवान द्वारा की जा रही है।





"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100